page 1 and 8 Feb 5_page 1 Mar 25 final ds.qxd 2/5/2026 1:39 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 अभिनव थियेटर में बहुप्रतीक्षित 'आप हमारे हैं कौन' नाटक का होगा मंचन

5 विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डोमाराजू नार्वे चेस 2026 में खेलेंगे

8 जैविक खाद- रसायनिक खादों का सार्थक विकल्प

मौसम जम्मू न्यूनतम 10 अधिकतम 19

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-32 | जम्मू तवी, वीरवार 05 फरवरी, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

लोकसभा में विपक्ष के बार-बार हंगामें के बीच कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली, 04 फ़रवरी । विपक्ष के भारी हंगामें के कारण बुधवार को लगातार तीसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बार-बार के व्यवधान और तीन स्थगनों के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते पहले 12 बजे और फिर 02 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई लेकिन वह भी अधिक देर तक नहीं चल सकी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शाम 05 बजे तक के लिए स्थगित की गई। शाम को भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा को अगले दिन गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कुछ पुस्तकों का हवाला दिया। निशिकांत ने कहा कि एक किताब पर

चर्चा चल रही है, किताब प्रकाशित नहीं हुई है। वे उन किताबों के बारे में बताना चाहते हैं जिनमें नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के बारे में लिखा गया है। यह किताबें छपी हुई हैं। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगातार विरोध किया, जिसके कारण कार्यवाही बाधित होती रही। पीठासीन अधिकारी ने उन्हें अध्यक्ष की व्यवस्था का हवाला देते हुए विषय से संबंधित बात रखने को कहा। दूसरी ओर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके चलते सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित कर दी गई।

शाम में कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी के बोलने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप तक पहुंच गए, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर पिछले दो दिनों से विवाद बना हुआ है। राहुल गांधी पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक से जुड़े संदर्भ रखना चाहते थे, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई।

किश्तवाड़ और उधमपुर में दो मुठभेड़ों में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी ढेर

जम्मू तवी, 4 फरवरी। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में बुधवार को हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के तीन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। यहां रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी-I के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ क्षेत्र के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चल रहे तलाशी अभियान के दौरान शाम करीब 5.45 बजे डिच्छर, चतरू के सामान्य क्षेत्र में आतंकियों के साथ फिर से संपर्क स्थापित हुआ। इस अभियान में सीआईएफ डेल्टा, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। वहीं उधमपुर जिले में बुधवार को दो पाकिस्तानी आतंकियों को उस समय ढेर कर दिया गया जब वे एक गुफा के अंदर फंसे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि इनमें जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर भी शामिल था। दोपहर के समय जब सुरक्षा बलों ने गुफा पर धावा बोला तो कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अधिकारियों के अनुसार मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान रुबानी उर्फ अबू माविया के रूप में हुई है,

जो जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर था और पिछले कई वर्षों से इस इलाके में सक्रिय था। एक आतंकी का शव गुफा के मुहाने पर पड़ा मिला, जबकि दूसरे का शव गुफा के अंदर गहराई में मिला। अधिकारियों ने बताया कि सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मंगलवार शाम करीब 4 बजे रामनगर-बसंतगढ़ क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों का पता लगाया, जिसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना ने इस 20 घंटे से अधिक चले अभियान को ऑपरेशन किया नाम दिया और कहा कि भले ही अभियान समाप्त हो चुका है, लेकिन इलाके में अभी भी निगरानी जारी है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप, भाजपा विधायकों का वॉकआउट

जम्मू, 04 फरवरी । सदन में बोलने के लिए विपक्ष को समय देने में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सभी भाजपा सदस्यों ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा से बहिर्गमन किया।सदन से बाहर निकलने से पहले भाजपा विधायकों और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने और चयनित अधिकांश छात्रों के मुस्लिम समुदाय से होने के बाद माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का आरोप लगाया। जब स्पीकर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तो भाजपा नेताओं ने एनसी विधायक सज्जाद शाहीन को दिए गए समय पर सवाल उठाया, जो उस समय उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को अधिक समय दिया जा रहा है, जबकि उनके सदस्यों को बार-बार नजरअंदाज किया जा रहा है या कम किया जा रहा है। हालांकि, अध्यक्ष ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वह सदन को स्थापित नियमों और परंपराओं के अनुसार सख्ती से चला रहे हैं।

बडगाम में 20 सरकारी कार्यालय किराए की इमारतों में, एकीकृत परिसर की कोई योजना नहीं - सरकार

जम्मू, 04 फ़रवरी । जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज विधानसभा को सूचित किया कि बडगाम जिले में 20 सरकारी कार्यालय किराए की इमारतों से चल रहे हैं और उप-जिला स्तर पर एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में प्रस्तुत लिखित उत्तर के अनुसार लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग ने बताया कि वर्तमान में बडगाम जिले में विभिन्न विभागों के 20 सरकारी कार्यालय किराए की इमारतों से चल रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग में लगभग 10 हजार पद खाली : सरकार

जम्मू, 04 फ़रवरी । जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भारी जनशक्ति की कमी का सामना कर रही है। स्वास्थ्य संस्थानों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 10 हजार पद खाली पड़े हैं।

बडगाम विधायक आगा मुंतजिर मेहदी के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बड़े पैमाने पर रिक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि सरकार सभी स्वीकृत पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सदन में साझा किए गए विवरण के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू में 538 राजपत्रित और 904 गैर-राजपत्रित रिक्त पद हैं जबकि जीएमसी श्रीनगर में 434 राजपत्रित और 174 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की कमी है।

जीएमसी बारामूला में 1,304 स्वीकृत पदों में से 431 रिक्तियां हैं, जबकि जीएमसी अनंतनाग में 1,098 स्वीकृत पदों में से 424 रिक्त पद हैं। जीएमसी राजौरी को 125 संकाय पदों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और जीएमसी उधमपुर में 799 स्वीकृत पदों में से 668 रिक्तियां हैं। परिवार कल्याण विभाग में 2,276 स्वीकृत पदों में से 573 पद रिक्त हैं। सदन को बताया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, कश्मीर (डीएचएसके) 388 राजपत्रित और 2,797 गैर-राजपत्रित रिक्तियों से जूझ रहा है, जिससे पूरी घाटी में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएँ गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

इसी तरह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू (डीएचएसजे) 1,489 रिक्त पदों से जूझ रहा है। मंत्री सकीना इटू ने कहा कि इन रिक्तियों को भरने से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

जम्मू-श्रीनगर मेट्रोलाइट के लिए डीपीआर केंद्र को भेजी गई, अंतिम मंजूरी का इंतजार : सरकार

जम्मू, 04 फरवरी । जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि जम्मू और श्रीनगर के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड मेट्रोलाइट सिस्टम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचए) को मूल्यांकन और वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत कर दी गई है।

सरकार ने कहा कि केंद्र से अंतिम प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। सदन में प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रशासनिक परिषद ने 13 फरवरी, 2021 को इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसके बाद जम्मू के लिए 4,069.48 करोड़ रुपये और श्रीनगर के लिए 4,892.51 करोड़ रुपये की अनुमानित डीपीआर तैयार कर एमओएचए और भारत सरकार को विचारार्थ भेज दी गई। सरकार ने कहा कि परियोजनाओं में दोनों राजधानियों के लिए एलिवेटेड मेट्रोलाइट कॉरिडोर बनाने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने यह भी बताया कि डीपीआर (विस्तृत शोधपत्र) केंद्र में जांच के अधीन हैं। जवाब में कहा गया कि अभी तक केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अंतिम मंजूरी या वित्तपोषण प्रतिबद्धता की प्रतीक्षा है। सरकार ने विधानसभा को आगे बताया कि मेट्रोलाइट प्रणाली को मंजूरी मिलने के बाद इससे बढ़ते यातायात जाम को कम करने, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने और दोनों शहरों में नियोजित शहरी विकास को समर्थन देने की उम्मीद है। हालांकि केंद्र के निर्णय के लंबित होने के कारण इसके प्रारंभ या संचालन की कोई समयसीमा नहीं बताई गई। सरकार ने आगे कहा कि लगभग 8,962 करोड़ रुपये की संयुक्त परियोजना लागत प्रस्तावित प्रणालियों के पैमाने और उनके कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय निधि पर निर्भर है।

राजौरी-पुंछ के विधायकों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बाहर धरना दिया

जम्मू, 04 फरवरी । राजौरी और पुंछ के कई विधायकों ने बुधवार को विधान सभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन विधायकों ने पीर पंजाल क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में मौजूद नहीं होने का दावा करके कथित तौर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विपक्ष के नेता से माफी मांगने की मांग की।

दरअसल, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में कोई पीर पंजाल क्षेत्र नहीं है। यह मुद्दा सदन में कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने उठाया, जिसके बाद सदन में भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के कारण हंगामा मच गया। इसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐजाज जान, कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद, जावेद इकबाल, मुजफ्फर इकबाल खान और चौधरी अकरम ने पीर पंजाल के पक्ष में नारे लगाते हुए सदन के बाहर धरना दिया।

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जब तक विपक्ष के नेता सुनील शर्मा माफी नहीं मांगते, तब तक हम सदन को चलने नहीं देंगे। उन्होंने पीर पंजाल के लोगों का अपमान किया है। उन्हें पीर पंजाल के नाम का सम्मान करना चाहिए, जो लंबे समय से जाना जाता है।

साधना टॉप पर रात भर हुई भारी बर्फबारी के बाद फंसे 35 वाहनों को निकाला गया सुरक्षित

कुपवाड़ा, 04 फ़रवरी । कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने भारी बर्फबारी के कारण फंसे कम से कम 35 वाहनों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाल लिया।

एक अधिकारी के अनुसार, बुधवार को कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने सदना टॉप पर भारी बर्फबारी के बाद फंसे दर्जनों वाहनों को सुरक्षित निकाला।

अधिकारियों ने बताया कि प्रतिकूल मौसम और कम दृश्यता के बावजूद समन्वित टीमों ने देर रात तक काम किया और भारी बर्फबारी के कारण फंसे वाहनों को निकालने के लिए सुबह तक काम जारी रखा। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान कम से कम 35 फंसे वाहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

उन्होंने बताया कि बचाव कार्य युद्धस्तर पर किया गया जिसमें बर्फ हटाने वाली मशीनरी और फील्ड टीमों को तैनात किया गया ताकि यात्रियों को और अधिक परेशानी न हो और किसी भी चिकित्सा या मौसम संबंधी आपात स्थिति से बचा जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि संवेदनशील इलाकों को खाली कराने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि ताजा हिमपात के बाद सदना टॉप पर स्थिति तेजी से बिगड़ गई जिससे यातायात बाधित हो गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन के समय पर हस्तक्षेप से यातायात आंशिक रूप से बहाल हो सका और स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सका। प्रशासन ने यात्रियों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी और मौसम की स्थिति सामान्य होने तक यातायात निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

अधिकारियों ने कहा कि मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सड़क सुरक्षा और जनसुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का संसद को आश्वासन अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में खाद्य और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का रखा गया है पूरा ध्यान

नयी दिल्ली, 04 फरवरी । भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की जानकारी संसद के बाहर दिये जाने पर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद बुधवार को सरकार ने संसद को आश्वस्त किया कि इस समझौते में देश के खाद्य एवं कृषि क्षेत्र की प्रमुख संवेदनशीलताओं का पूरा ध्यान रखा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद के दोनों सदनों में दिये गये वक्तव्यों में कहा कि भारत समझौते में अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अमेरिका के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं।उन्होंने

कहा कि यह समझौता लघु एवं मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नये अवसर खोलेगा, उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगा और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इन्नोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले वर्ष फरवरी की अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। श्री गोयल ने कहा कि इन वार्ताओं के दौरान लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार-विमर्श के बाद, दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी से जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर

जम्मू, 04 फ़रवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी से जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें होने की उम्मीद है, जिनका उद्देश्य समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति और चल रही शासन एवं अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना है।

भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने गृह मंत्री के दौरे को जम्मू-कश्मीर के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत बताया। उन्होंने बताया कि ऐसे दौरे सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ाते हैं और आतंकवाद एवं अस्थिरता के प्रति सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की पुष्टि करते हैं।

रंधावा ने कहा कि गृह मंत्री का जम्मू दौरा हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। इस तीन दिवसीय दौरे के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ेगा। यह दौरा दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डीजी आईटीबीपी ने लद्दाख के उपराज्यपाल से की मुलाकात

लेह, 4 फरवरी। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज आईटीबीपी के महानिरीक्षक अखून साबरवाल के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल से लेह में शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान महानिदेशक ने उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तैनात आईटीबीपी कर्मियों की परिचालन तैयारियों, तैनाती और उनके कल्याण से संबंधित उपायों की जानकारी दी। बैठक में सीमा प्रबंधन, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों तथा नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।उपराज्यपाल ने अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कठोर जलवायु में देश की सीमाओं की रक्षा में आईटीबीपी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बल की प्रतिबद्धता के साथ-साथ आपदा प्रबंधन और क्षेत्र में सामुदायिक सेवा के लिए इसके योगदान की भी प्रशंसा की। इस अवसर पर उपराज्यपाल के सचिव डॉ. एल. फ्रैंकलिन भी उपस्थित थे।

घाटी में बेहतर हालात के बीच माइग्रेंट रिलीफ रजिस्ट्रेशन सही नहीं: मुख्यमंत्री उमर

जम्मू, 04 फ़रवरी । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि घाटी में कानूनऔर व्यवस्था की बेहतर स्थिति को देखते हुए कश्मीर माइग्रेंट रिलीफअसिस्टेंस के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए नए मामलों पर अभी विचार नहींकिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए प्रधानमंत्रीका रिटर्न और रिहैबिलिटेशन पैकेज का मकसद घाटी में उनकी अपनीमर्ज़ी से, सुरक्षित और इज्ज़तदार वापसी को आसान बनाना है, साथ हीघर, रोज़गार और दूसरे मदद के तरीकों से सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा भीपक्की करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य मुबारक गुल के असेंबली मेंलिखे सवाल का जवाब देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, फ्कश्मीर माइग्रेंटरिलीफ असिस्टेंस

के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए नए मामलों पर अभी विचारनहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर 12 जुलाई, 2023 को चीफ सेक्रेटरीकी अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में विचार किया गया, जिसमें यह पायागया कि घाटी में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति इस समय नएरजिस्ट्रेशन को सही नहीं ठहराती है।

एसएमएस की बीमारी युवाओं पर भारी

बिना बात की बात करने में माहिर युवाओं को एसएमएस की लत महंगी साबित हो रही है। इससे उनकी जेब तो ढीली हो ही रही है, उनकी रातों की नींद हराम होने के साथ ही मानसिक शांति भी गायब सी होती जा रही है। इस समस्या से सबसे ज्यादा पीड़ति हो रहे हैं टीनएजर्स, क्योंकि एसएमएस का चस्का उनमें सबसे ज्यादा है। एसएमएस की लतों से मानसिक रूप से परेशान और बैचेन अनेक युवा इन दिनों मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं।

एसएमएस की वजह से क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं और इनसे किस तरह निजात पाई जा सकती है, जानें एक्सपर्ट सलाह पर आधारित जितेंद्र सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। कंपनियों द्वारा कम पैसे में दी गई एसएमएस की सुविधा युवाओं के लिए दुविधा साबित हो रही है। मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे ज्यादातर मामलों में यह बात सामने आई है कि एसएमएस की लत मानसिक शांति और सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इससे क्रोध बढ़ने के अलावा बैचेनी और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो रही हैं। यही नहीं, एसएमएस का लगातार प्रयोग करने वाले युवाओं में अवसाद के साथ ही डर की भावना भी पैदा हो रही है। दरअसल, एसएमएस के जरिए दोस्तों से हर वक्त संपर्क में रहने के चलते युवाओं की दिनचर्या पूरी तरह गड़बड़ा गई है, इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। देर रात तक मोबाइल में संदेश के माध्यम से बात करने के कारण अधिकांश युवा गहरी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। कुछ रोचक मामलों में यह भी शामिल है कि अधिकांश युवा अक्सर अपने मोबाइल को इसलिए देखते रहते हैं कि शायद कोई एसएमएस आया हो, लेकिन प्राय: उनके लिए कोई एसएमएस नहीं होता। कई युवा तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने सहपाठियों से एसएमएस का जवाब नहीं मिलने पर वह निराशा और चिंता में भी डूब गए हैं, इससे उनके मन में एक तरह का अवसाद घर कर गया है कि कोई उनके संपर्क में रहना पंसद नहीं कर रहा है।

युवाओं से बातचीत में यह खुलासा हुआ कि वह बिना किसी वाजिब वजह के प्रतिदिन 150-200 तक एसएमएस कर देते हैं। इस मामले में टीनएजर्स युवतियां लड़कों से कहीं आगे हैं, क्योंकि लड़के जहां 50-100 एसएमएस ही कर पाते हैं, जबकि लड़कियां रोजाना 200 एसएमएस तक करती हैं। मजे की बात यह है कि एसएमएस के इस सिलसिले में बिना बात की बात या यूं कहें कि टाइम पास करने के लिए बेतुकी बातें ही होती हैं। इसमें सुबह से लेकर रात्रि तक की रूटीन बातें, पसंद-नापसंद, हॉबी, गपशप, घुमने-फिरने तक की बातें शामिल हैं।

यह समस्याएं आ रहीं सामने

मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य ने बताया कि फिलहाल एसएमएस की लत से परेशान हो चुके युवाओं के जो मामले उनके पास आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा शिकायतें अनिद्रा, अवसाद, कम भूख, ब्रेन ट्यूमर, गुस्सा, बैचेनी और क्रोधित होने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनके पास आने वाले ज्यादातर युवाओं में यह शिकायत आम है कि वह सोते समय मोबाइल अपने पास में ही रखते हैं, इससे वह पूरी नींद नहीं ले पाते, क्योंकि एसएमएस आने या मोबाइल पर कॉल आते ही उनकी नींद खुल जाती है। प्राय: एसएमएस मिलने पर युवा नींद तोड़कर उसे पढ़ते हैं, जिससे उनकी नींद प्रभावित हो रही है।

ज्यादातर युवाओं में यह शिकायत भी है कि वह मैसेज की आशंका से हर कुछ ही सैकंड के बाद अपना मोबाइल देखते हैं और लगातार मैसेज टाइप करने की वजह से उनके अंगूठे और कलाई के बीच दर्द रहता है।

इसी तरह वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ आरएन साहू ने बताया कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें युवाओं ने स्वीकार किया है कि यदि वह एसएमएस करते हैं और रिप्लाई नहीं मिलता तो वह बैचेन हो जाते हैं और उनमें हीनभावना आने लगती है। इस स्थिति को टेक्स्टाफ्रेनिया कहा जाता है। उन्होंने बताया किए ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं।

ऐसे पाएं निजात

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ आरएन साहू कहते हैं कि इस समस्या से छुटकारा पाने का बेहतर रास्ता तो यही है कि मोबाइल का उपयोग कम से कम किया जाए। एसएमएस ही नहीं, बल्कि बातचीत में भी इसका उपयोग सीमित हो, क्योंकि यह सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

युवाओं को चाहिए कि वह जरूरी होने पर ही एसएमएस करें। एसएमएस को गप्पबाजी या टाइम पास का माध्यम न बनाएं। जितनी भी बातें करनी है वह मिलकर करें। खासकर देर रात तक एसएमएस से बात करने से बचें एवं सोते समय मोबाइल अपने पास में न रखें, बेहतर होगा कि सोने से पहले मोबाइल बंद कर दें।

अकेलापन मिटाने का जरिया

एक मेडिकल स्टूडेंट बताते हैं कि वह रोजाना 100 से अधिक एसएमएस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एसएमएस से बातें करना अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है और अकेलेपन से भी मुक्ति मिल जाती है। स्टूडेंट ने यह स्वीकार करते हैं कि इससे उनकी पढ़ाई बेहद प्रभावित हुई है और नींद भी उड़ गई है, क्योंकि कई बार उन्हें नींद में भी ऐसा लगता है कि मोबाइल पर कोई एसएमएस आया है, इससे नींद खुल जाती है।

इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रूपेश त्यागी का कहना है कि मेरे लिए एसएमएस नए-नए दोस्त बनाने का जरिया है और मैं इसके लिए हमेशा एसएमएस का सहारा लेता हूं, क्योंकि यह सस्ता भी है। लेकिन फिलहाल वह एसएमएस से बेहद परेशान हो चुके हैं, उनका कहना है कि शुरू में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब इतने अधिक एसएमएस आने लगे हैं कि मोबाइल देखकर ही सिरदर्द होने लगता है और मैं कभी-कभी एसएमएस भेजने वाले दोस्तों पर क्रोधित हो जाता हूं।

अगर खुजली से हैं परेशान तो इन्हें आजमाइए

खुजली एक त्वचा रोग है, जिससे व्यक्ति काफी परेशान और निराश हो जाता है। खुजली के लिए सबसे कारगर उपाय है तेल की मालिश जिससे रूखी और बेजान त्वचा को नमी मिलती है। चलिए जानते हैं खुजली के कुछ घरेलू इलाज।

1. खुजली होने पर प्राथमिक सावधानी के तौर पर सफाई का पूरा ध्यान रखिए।
2. साबुन का प्रयोग जितना भी हो सकता है कम कर दें और सिर्फ मृदु साबुन का ही प्रयोग करें।
3. कभी कभी त्वचा को सुगंधित पदार्थों, क्रीम, लोशन, शैंपू, जूतों या कपड़ों में पाए जाने वाले रसायनों से भी एलर्जि हो जाती है। इसलिए सही तरीके का लोशन इत्यादि ही लगाएं।
4. अगर आपको कब्जा है तो उसका भी इलाज करवाएं।
5. हफ्ते में दो बार मुल्तानी मिट्टी और नीम की पत्ती का लेप लगाएं, उसके बाद साफ पानी से शरीर को धो लें।
6. थोडा सा कपूर लेकर उसमें दो बड़े चम्मच नारियल का तेल मिलाकर खुजली वाले स्थान पर नियमित लगाने से खुजली मिट जाती है। हां, तेल को हल्का सा गरम करके ही कपूर में मिलाए।
7. यदि जनेंद्रिय पर खुजली की शिकायत हो, तो गर्म पानी में फिटकरी मिलाकर उसे लगाएं।
8. नारियल तेल का दो चम्मच लेकर उसमें एक चम्मच टमाटर का रस मिलाइए। फिर खुजली वाले स्थान पर भली प्रकार से मालिश करिए। उसके कुछ समय बाद गर्म पानी से स्नान कर लें। एक सप्ताह ऐसा लगातार करने से खुजली मिट जाएगी।
9. यदि गेहूं के आटे को पानी में घोल कर उसका लेप लगाया जाए, तो विविध चर्म रोग, खुजली, टीस, फोडे-फुंसी के अलावा आग से जले हुए घाव में भी राहत मिलती है।
10. सवेरे खाली पेट 30-35 ग्राम नीम का रस पीने से चर्म रोगों में लाभ होता है, क्योंकि नीम का रस रक्त को साफ करता है।
11. खुजली से परेशान लोगों को चीनी और मिठाई नहीं खानी चाहिए। परवल का साग, टमाटर, नीबू का रस आदि का सेवन लाभप्रद है।

जुकाम में खूब खाएं, बुखार में नहीं

एक कहावत है, फीड ए कोल्ड, स्टार्व ए फीवर। यानी जुकाम के समय खूब खाओ और बुखार के समय भूखे रहो। लगता है इस कहावत में कुछ दम है। भरपेट खाने और भूखे रहने के असर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर एकदम अलग-अलग होते हैं। वैसे डॉक्टर उक्त कहावत को ज्यादा महत्व नहीं देते। एम्सटर्डम के एकेडमिक मेडिकल सेंटर में किए गए अनुसंधान से कुछ रोचक परिणाम प्राप्त हुए हैं। पता चला है कि भरपेट भोजन करने से प्रतिरक्षा तंत्र का एक पक्ष प्रेरित होता है। यह जुकाम पैदा करने वाले वायरसों का सफाया करता है, जबकि भूखे रहने से प्रतिरक्षा तंत्र का वह पक्ष सक्रिय होता है, जो बुखार के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया का सामना करता है। सेंटर के वैज्ञानिक गिस वान डेन ब्रिन्क और उनके साथियों ने एक क्रिसमस दावत के दौरान अतिथियों के रक्त के नमूने प्राप्त किए। वे देखना चाहते थे कि क्या प्रतिरक्षा तंत्र पर अल्कोहल का कोई असर होता है? पता चला कि अल्कोहल का तो कोई असर नहीं होता, लेकिन भोजन का असर अवश्य होता है। यह देखकर वैज्ञानिकों ने छह लोगों से अनुरोध किया कि वे एक रात भूखे रहें और फिर अगले दिन सुबह प्रयोगशाला में आएं। इन्हीं लोगों को एक बार तरल भोजन देकर भी परीक्षण किए गए। देखने में आया कि तरल भोजन के लगभग 6 घंटे बाद उनके खून में गामा इंटरफेरॉन की मात्रा सामान्य से चौगुनी हो गई थी। गामा इंटरफेरॉन उन तमाम कोशिकाओं को नष्ट करती है, जिसमें कोई विषाणु (वायरस) घुस चुका हो। यह प्रतिरक्षा मूलत: वायरसों के विरुद्ध काम करती है। लगता है कि भरपेट भोजन इसे बढ़ावा देता है। दूसरी ओर, जब इन्हें सिर्फ पानी पिलाया गया तो उनमें इंटरफेरॉन की मात्रा में तो थोड़ी सी कमी आई मगर एक अन्य रासायनिक संदेशवाहक इंटरल्यूकीन-4 की मात्रा चौगुनी हो गई। इंटरल्यूकीन-4 हमारी कोशिकाओं के बाहर मंडराते रोगजनक तत्वों पर हमला करता है। बैक्टीरिया आमतौर पर यही करते हैं, कोशिकाओं के बाहर टहलते रहते हैं। इनमें से कई बैक्टीरिया बुखार के कारक हैं। वैसे ब्रिन्क ने चेतावनी दी कि यह एक बहुत छोटा सा अध्ययन है। लोगों को इसके आधार पर अपने तौर-तरीके बदलने की उतावली नहीं करनी चाहिए। वैसे एक अन्य अध्ययन ने भी इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। एम्सटर्डम के ही फ्री यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में किए गए इस अध्ययन में पता चला है कि ग्लूटैमीन नामक एक अमीनो अम्ल भी इंटरफेरॉन जैसी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है।

वजन कम ना होने के पांच मुख्य कारण

अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बार-बार जिम जाने से भी आपके वजन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। पूरी तरह से वजन कम करने के लिए कई ऐसे उपाए हैं जो काफी कारक हैं। जिनमें से सही तरीके से लिया गया आहार और व्यायाम सर्वक्षेष्ठ स्थान रखता है। पर इसके अलावा भी ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके वजन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं इन्हीं कारणों की।

पांच महत्तवपूर्ण कारण क्या हैं-

1. अनुचित डाइट प्लैन: आपको जरुरत है ऐसी आहार योजना कि जो खास आपके शरीर की जरुरत के हिसाब से तैयार की गई हो। इसको तैयार करने के लिए यह देखना बहुत जरुरी है कि आप कौन सा कार्य करते हैं और आपकी रोज़ की दिनचर्या कैसी है। अगर आप रोज़ जिम जाते हैं और वापस घर पर आकर दिन भर सोते रहते हैं तो किसी भी प्रकार का डाइट प्लैन अपको पतला नहीं कर पाएगा।

2. ब्रेकिगं प्वांइट: यहां पर ब्रेकिगं प्वांइट हम उसे कहते हैं, जिस समय ब्यक्ति का वजन कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसा सोंचते हैं कि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ही आपका वजन कम होने लगेगा तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले शरीर में से पानी, फिर ऊर्जा और अंत में वसा कम होना शुरु होता है। हर ब्यक्ति का ब्रेकिगं प्वांइट अलग अलग होता है। जहां कई लोग चार ही दिनों में किलो भर वजन कम कर लेते हैं, वहीं पर कुछ लोगों का वजन दो हफ्ते बाद भी वैसा ही रहता है। इसलिए आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

3. व्यायाम की सही योजना: अगर आप काफी समय से सिर्फ वही पुरानी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी एक्सरसाइज को कुछ कुछ दिनों या महीनों पर परिवर्तित कर लेना चाहिए।

4. कार्डियो और वेट ट्रेनिगं का उचित मिश्रण: वर्कआउट हमेशा इन्ही दो महत्वपूर्ण भागों में बंटा होता है। आपको वजन कम करने के लिए हमेशा 80 प्रतिशत कार्डियो करना चाहिए। जिसमें ट्रेडमिल, साइकिलिगं और जौगिगं शामिल होती है। वेट ट्रेनिगं मासपेशियों को टोन करने के लिए किया जाता है।

5. हार्मोनल असंतुलन: अगर फिर भी आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो शायद शरीर में आंतरिक रूप से ही कोई समस्या हो। थाइरॉइड ग्लैन्ड के सही से काम ना कर पाने की वजह से भी वजन कम नहीं होता चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यूं ना कर लें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

अभिनव थियेटर में बहुप्रतीक्षित 'आप हमारे हैं कौन' नाटक का होगा मंचन

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण आने वाला है, जब पद्मश्री सम्मानित रंगकर्मी बलवंत ठाकुर द्वारा लिखित व निर्देशित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित नाट्य प्रस्तुति 'आप हमारे हैं कौन' का मंचन अभिनव थियेटर, जम्मू में 6, 7 और 9 फरवरी 2026 को सायं 5 बजे किया जाएगा। ये विशेष प्रस्तुतियाँ दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में प्रस्तुति से पूर्व जम्मू के दर्शकों के लिए समर्पित की गई हैं। इस नाटक का अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के लिए चयन जम्मू के थिएटर आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है जिससे स्थानीय युवा कलाकारों को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन सभी प्रस्तुतियों का प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है।

पद्मश्री बलवंत ठाकुर ने इस अवसर को जम्मू के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव बताते हुए आम जनता से अपील की कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। उन्होंने विशेष रूप से अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को यह नाटक दिखाने अवश्य लाएं क्योंकि जम्मू में बच्चों और युवा मन को केंद्र में रखकर तैयार किया गया गुणवत्तापूर्ण रंगमंच बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि रंगमंच केवल कलाकारों को ही नहीं, बल्कि दर्शकों को भी गहराई से प्रभावित करता है।

समर्पण दिवस से पहले अशोक कौल ने पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा की

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। भाजपा जम्मू-कश्मीर के महासचिव (संगठन) अशोक कौल ने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक व्यापक संगठनात्मक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पहुंच का आकलन किया गया।उनके साथ भाजपा जम्मू-कश्मीर के महासचिव संजीता डोगरा, बलदेव सिंह बिल्लावारिया और गोपाल महाजन भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और विभिन्न स्तरों पर की जा रही संगठनात्मक गतिविधियों और जन संपर्क पहलों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी।

विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य जनता के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने और इसकी संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कौल ने केंद्रीय बजट 2026 जनजागरण अभियान, वीबी ग्राम जी और अन्य पार्टी पहलों के तहत आयोजित सम्मेलनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन चौपालों, विधानसभा सम्मेलनों और युवा, किसान और महिला सम्मेलनों सहित विशेष जन संपर्क कार्यक्रमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

जीजीएम साइंस कॉलेज में मिशन युवा-उद्यम जागृति पर जागरूकता कार्यक्रम

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल (जीजीएम) साइंस कॉलेज, जम्मू में मिशन युवा-उद्यम जागृति 4.0 युवाओं की उद्यमशील क्षमता को सशक्त बनाना विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) रोमेश कुमार गुप्ता के संरक्षण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. मोना सेठी, संयोजक छात्र कल्याण एवं मॉनिटरिंग समिति के स्वागत भाषण से हुई जिसमें उन्होंने छात्रों को मिशन युवा के उद्देश्य और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर मिशन युवा के नोडल अधिकारी एवं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन, उधमपुर के

एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विशाल शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने 'उद्यम जागृति 4.0' ढांचे पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पहल शैक्षणिक ज्ञान और औद्योगिक अनुप्रयोग के बीच की दूरी को कम करने पर केंद्रित है। उन्होंने सरकारी सहायता, डिजिटल कौशल और उद्यम से जुड़े अवसरों की जानकारी भी साझा की।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और सेमेस्टरों के 150 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। सत्र के उपरांत प्रश्नोत्तर एवं संवाद के दौरान छात्रों ने पारंपरिक करियर विकल्पों से आगे बढ़कर उद्यमिता की दिशा में संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. वंदना खजूरिया ने की।

उपायुक्त ने मिशन युवा कार्यक्रम के तहत 458 मामलों को मंजूरी प्रदान की

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। बारामूला के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने आज डीसी कार्यालय के बैठक कक्ष में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति बारामूला की बैठक की अध्यक्षता की और मिशन युवा कार्यक्रम के तहत 458 नए मामलों को मंजूरी दी।

अध्यक्ष को पिछली डीएलसी बैठकों में स्वीकृत मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और जिले के बेरोजगार पात्र युवाओं के कई नए मामले समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

मामलों की गहन समीक्षा के बाद, डीसी ने 458 मामलों को मंजूरी दी, जिससे उन्हें स्वरोजगार के रास्ते तलाशने और अपनी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार करने का अवसर मिलेगा।

कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए, डीसी ने आवेदनों के सुचारू प्रसंस्करण और इच्छुक उद्यमियों को निरंतर मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया।

डीसी ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समय पर तैयार करने का निर्देश दिया ताकि वित्तीय सहायता लाभार्थियों तक बिना किसी देरी के पहुंच सके।

बैठक में सहायक निदेशक रोजगार, बारामूला; लीड जिला प्रबंधक; क्लस्टर प्रमुख, जम्मू-कश्मीर बैंक; जिला महाप्रबंधक, नाबार्ड सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नगरी में दहशत फैलाने वाला लुटेरा गिरफ्तार

कठुआ । कठुआ जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर नगरी क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही मारपीट और लूटपाट की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। खासतौर पर नगरी के दराला गांव में एक शख्स लोगों पर हमला कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित थे। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस पर नगरी पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि दो दिनों के भीतर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मंगलवार को नगरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दराला गांव निवासी एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया, जो नगरी क्षेत्र में हुई दो बड़ी वारदातों में शामिल बताया जा रहा है। आरोपी लोगों पर हमला कर लूटपाट करता था और इलाके में डर का माहौल पैदा कर रहा था। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व चैकी अधिकारी रविंद्र सिंह ठाकुर की टीम ने किया, जिनकी तत्परता और सटीक कार्रवाई से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे, वारदातों की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती थी, और क्या पिछले एक महीने में हुई अन्य लूटपाट की घटनाओं से भी इसका संबंध है। नगरी पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को आरोपी या उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी है तो वह पुलिस को सूचित करें।

आरबीए आरक्षण में कटौती के खिलाफ पब्लिक वेलफेयर फोरम का विरोध

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। पब्लिक वेलफेयर फोरम के चेयरमैन अमर नाथ ठाकुर ने आज प्रेस क्लब जम्मू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आरबीए (रिज़र्वेशन फॉर रेज़डिंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज़) और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में प्रस्तावित कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और आरबीए क्षेत्रों के लोगों के साथ खुला अन्याय करार दिया। ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2020 में अनुच्छेद 370 के बाद आरबीए आरक्षण को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया और अब इसे 7 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे आरबीए और ईडब्ल्यूएस वर्गों के साथ लगातार हो रहा भेदभाव

बताया।

उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मंत्रिमंडल के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष एवं जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सभी विधायकों से अपील की कि आरक्षण पर एक व्यापक और संवैधानिक विधेयक विधानसभा में लाया जाए, जिससे सभी आरक्षित वर्गों को समान और न्यायपूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) तथा अगस्त 2024 के सात-सदस्यीय पीठ के फैसलों का हवाला देते हुए तर्कसंगत आरक्षण नीति लागू करने की मांग की। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आरबीए क्षेत्रों के कई विधायकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। फोरम ने मांग की कि वर्तमान 10 प्रतिशत आरबीए आरक्षण को एसटी-2 में विलय किया जाए और एसटी-2 आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए, ताकि आरबीए क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके।

ठाकुर ने कहा कि आरबीए आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों में लागू नहीं होता जिससे इन क्षेत्रों के छात्र और युवा गंभीर रूप से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि आरबीए क्षेत्रों में रहने वाले लोग भौगोलिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एसटी समुदाय के समान परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। फोरम ने क्रीमी लेयर को सभी आरक्षित वर्गों से बाहर करने, बार-बार लाभ लेने वाले सक्षम परिवारों की पहचान तथा वास्तविक रूप से गरीब और वंचित परिवारों को ही आरक्षण का लाभ देने की भी मांग की। अंत में चेतावनी दी गई कि यदि आरबीए की मांगों की अनदेखी जारी रही तो जन असंतोष और तेज होगा। प्रेस वार्ता में बशीर अहमद, मोहम्मद सलीम शेख, मुश्ताक अहमद, विजय शर्मा, हंस राज, सुभाष चंदर, बिशन दास ठाकुर, एस. परवीन सिंह, श्याम राज ठाकुर सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

रणविजय सिंह ने अर्नास के गौरी शंकर मंदिर का दौरा किया, महाशिवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा की

जम्मू, 04 फरवरी। जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी रणविजय सिंह ने आगामी महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनज़र आज रियासी जिले के अर्नास स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य तैयारियों की समीक्षा करना और पावन पर्व के दौरान धार्मिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना था।

दौरे के दौरान श्री रणविजय सिंह ने मंदिर परिसर की समग्र स्थिति का जायजा लिया और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं—जैसे स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं—की समीक्षा की। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तीर्थस्थल की पवित्रता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

ट्रस्टी ने मंदिर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की तथा सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री रणविजय सिंह ने जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा अपने प्रबंधनाधीन प्राचीन मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के संरक्षण, रखरखाव और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर भर में श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत ढांचे और सुविधाओं में सुधार हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए समर्पित है तथा अपने संरक्षण में आने वाले मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा।

दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के भूमि अभिलेख अधिकारी भी ट्रस्टी के साथ मौजूद रहे।

बुडगाम पुलिस ने टाउनहॉल बीरवाह में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन

बडगाम, 04 फ़रवरी (हि.स.)।

बुडगाम पुलिस ने टाउनहॉल बीरवाह में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से छात्रों और अन्य हितधारकों को उभरते साइबर खतरों और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना था।

इस कार्यक्रम में बीरवाह पुलिस स्टेशन के एसएचओ, बडगाम साइबर पुलिस स्टेशन के साइबर विशेषज्ञ और बडगाम जिला तकनीकी टीम (डीटीटी) के सदस्य उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को साइबर धोखाधड़ी के विभिन्न रूपों, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक किया गया।

विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे किसी के साथ भी ओटीपी, पासवर्ड और बैंक विवरण साझा करने से बचें, ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के दौरान सतर्क रहें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अज्ञात व्यक्तियों से बातचीत न करें।

प्रतिभागियों से अपने समुदायों में साइबर एंबेसडर के रूप में कार्य करने का आग्रह किया गया और उन्हें राष्ट्रीय साइबर अपराध अधिनियम सहित रिपोर्टिंग तंत्रों के बारे में जानकारी दी गई।

जम्मू नगर निगम की म्युनिसिपल वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू, 04 फरवरी (हि.स.)। जम्मू नगर निगम की म्युनिसिपल वर्कर यूनियन ने बुधवार को टाउन हॉल स्थित निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लंबित मांगों को लेकर यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग की।

यूनियन अध्यक्ष रिंकू गिल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार ज्ञापन देने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

यूनियन की प्रमुख मांगों में नगर निगम से एनजीओ सिस्टम को पूरी तरह समाप्त करना, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण, कर्मचारियों के लिए कॉलोनी की सुविधा, एक्स-ग्रेशिया राशि में बढ़ोतरी और एसआरओ से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निपटारा शामिल है।

प्रदर्शन के दौरान रिंकू गिल ने ऐलान किया कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 5 फरवरी को सचिवालय तक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 6 फरवरी से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है।

बरनोटी में मनरेगा कार्यों को लेकर लगे आरोप निराधार-बीडीओ

कठुआ, 04 फरवरी (हि.स.)। ब्लॉक बरनोटी में मनरेगा कार्यों में कथित फर्जी हाजिरी और फोटो को लेकर प्रकाशित समाचारों को लेकर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बरनोटी ने स्पष्टीकरण जारी किया है। बीडीओ ने स्पष्ट किया है कि संबंधित मनरेगा कार्यों में किसी भी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल की फोटो अपलोड करना केवल प्रारंभिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि मजदूरी भुगतान से पहले हाजिरी सत्यापन, मस्टर रोल की जांच और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। समाचार में पंचायत बौड़ा और माही चक से संबंधित जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, वे आधिकारिक मस्टर रोल और एमआईएस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। बीडीओ के अनुसार, कुछ मामलों में कार्यस्थल पर अतिरिक्त व्यक्ति की मौजूदगी का अर्थ हाजिरी नहीं होता और जिनका नाम मस्टर रोल में दर्ज नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता।

UT OF JAMMU AND KASHMIR
OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVERNMENT POLYTECHNIC JAMMU
Bikram Chowk, Jammu (J&K) 180-004
राजकीयबहुशिल्प , जम्मू
बिक्रम चौक, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)-180004
e-mail:govt-polyjammu@jk.gov.in

Sub:Engagement of Guest Faculty inGovernmnent Polytechnic Jammu.

ADVERTISEMENT NOTICE

Applications are invited from the eligible candidates for the engagement as Guest Faculty for the academic session May-June, 2026 as mentioned below

S.No	Discipline	Qualification
1	Medical Lab Technology	1. Bachelor's Degree in MLT with 55% marks from the recognized University 2. Diploma (First Class) in MLT from a recognized institution. (Preference shall be given to the candidate from category-1)

Application Form accompanied with self-attested copies of the following documents must reach the office of the undersigned by or before 07.02.2026:
1. Academic/Technical Qualification. (Certificate/Mark Sheets)
2. Domicile Certificate.
3. Experience Certificate, if any.

Terms and Conditions:-
1. The engagement shall be purely on need basis for one academic session May-June, 2026 only and the candidate will not claim for permanent absorption.
2. The selected candidates shall have to submit the undertaking/ affidavit from the First Class Magistrate before joining clearly indicating that he/she shall not claim for continuation/ regularization for his/her services after the completion of the session and shall follow the rules and regulations of the institution.
3. Selection shall be made purely on merit basis, 80 Points shall be kept for basic qualification (pro-rata basis), 05 points for higher qualification, 05 points for GATE/NET/SET and 05 jpoints for teaching experience.
Interaction session will scheduled on 09.02.2026 at 12:30 pm.
4. The selected candidates shall be paid @ Rs.750/- per lecture subject to the ceiling of Rs.20000/- per month.

No: GPJ/F-598/272-7593-95 Dated: 02.02.2026

DIP/J-11101/25
Dtd:3-2-2026

Sd/-
(Er. Talet Mahmood Shawl)
Principal

केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता क्विज का कॉलेज राउंड आयोजित

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू (सीयूजे) में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता क्विज (एनएफएलक्यू)-2026 के कॉलेज राउंड का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस प्रतियोगिता में व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रबंधन, अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग संकायों के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव जैन के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के डीन प्रो. ए.के. नंदा ने किया। उद्घाटन अवसर पर स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के मानव संसाधन प्रबंधन एवं संगठनात्मक व्यवहार विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. जया भसीन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश झा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अर्थशास्त्र विभाग के संकाय सदस्य भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर प्रो. जया भसीन ने एनएफएलक्यू पहल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) द्वारा आयोजित की जा रही एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। प्रो. राकेश झा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इससे पहले प्रो. ए.के. नंदा ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि यह क्विज छात्रों को बजट, निवेश, बचत और आर्थिक सिद्धांतों जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।

हैंडिक्राफ्ट कौशल पर जागरूकता व्याख्यान आयोजित

हीरानगर, 04 फरवरी (हि.स.)। राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में संस्थान नवाचार परिषद एवं उन्नत भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में हस्तशिल्प (हैंडिक्राफ्ट) कौशल पर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कठुआ के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने छात्रों को पारंपरिक हस्तशिल्प, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी।

आरसेटी के संसाधन व्यक्तियों अविनाश एवं अशोक ने छात्रों को हस्तशिल्प तकनीकों, छोटे व्यवसाय की शुरुआत, विपणन रणनीतियों और सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में बताया। स्वयं सहायता समूह की सदस्य सोनिया एवं बंदना ने अपने सफल अनुभव साझा कर छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना ने कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि रचनात्मकता को आजीविका का साधन बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन प्रो. नीरू शर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अनुपमा अरोड़ा ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में छात्रों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

संपादकीय

दिव्यांगों के लिए न्याय में देरी

यह अत्यंत विचारणीय है कि समय-समय पर जम्मू-कश्मीर में शासन करने वाली सरकारों के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांग समुदाय आज भी अपनी लंबित मांगों के कारण लगातार संकट और कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इन अधूरी मांगों ने इनके जीवन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसी संदर्भ में जम्मू-कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के बैनर तले दिव्यांग व्यक्तियों ने सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता और कानूनी संरक्षण से जुड़ी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है।

वर्तमान सरकार को इन मांगों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि समाज के इस वर्ग की जायज़ मांगें बिना किसी देरी या भेदभाव के पूरी की जा सकें। इस समुदाय की सबसे प्रमुख मांग पेंशन में वृद्धि की है, जो पूरी तरह से उचित है। बताया जाता है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जो आज के समय में नगण्य है। इस राशि से कोई व्यक्ति एक महीने का बिजली-पानी या ईंधन का खर्च भी वहन नहीं कर सकता, दवाइयों, राशन, परिवहन, सब्ज़ी-फल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की बात तो दूर है।

निश्चित रूप से यह मुद्दा सरकार द्वारा बिना किसी और देरी के उठाया जाना चाहिए, ताकि समाज के इस कमजोर वर्ग को न्याय मिल सके और वे गरिमा एवं आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंबे समय से इस समुदाय को मुफ्त बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के अधिकार से वंचित रखा गया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और इन सुविधाओं को सुनिश्चित करे, क्योंकि यह सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर, सरकार को इन मांगों को विशेष मामला मानते हुए बिना किसी बहाने या टालमटोल के शीघ्र पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह न्यायसंगत और वैध हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर सरकार को पश्चिमी देशों से प्रेरणा लेते हुए सार्वजनिक ढांचे का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि दिव्यांगजन बिना किसी पर निर्भरता के स्वतंत्र जीवन जी सकें। फुटपाथों का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि स्वचालित व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोग बिना किसी बाधा के उन पर चल सकें। शॉपिंग मॉल और छोटी दुकानों को भी व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों में दिव्यांगों के लिए अलग और सुविधाजनक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे सहज, स्वतंत्र और तनाव-मुक्त महसूस कर सकें। निम्न-फर्श (लो-फ्लोर) बसों की अवधारणा भी जम्मू-कश्मीर में ठीक से लागू नहीं हो पा रही है, जो इस समुदाय के प्रति शासन की उदासीनता को दर्शाती है।

इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि जम्मू-कश्मीर को दिव्यांग समुदाय के लिए एक बेहतर और समावेशी स्थान बनाया जा सके, क्योंकि यह शासन चलाने वालों की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

भारत के संबंध में वैश्विक स्थिति को कैसे बदल रहे हैं व्यापार समझौते

भारत की बदलती व्यापार नीतियों का लक्ष्य सिर्फ एक्सपोर्ट और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अर्थव्यवस्था को वैश्विक नेतृत्व के लिए फिर से स्थापित करना है। व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों और सरल टैरिफ प्रणालियों के साथ उत्पादों और सेवाओं के उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। भारत हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, श्रम-गहन एक्सपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत मुक्त व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित करके साल 2032 तक .10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की नींव रख रहा है। इन सुधारों का मकसद लंबे समय में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और नौकरियां पैदा करना भी है, खासकर भारत के युवाओं के लिए।

-डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

भारतीय उत्पादन और सेवाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करने और निवेश अवसरों को बढ़ावा देकर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की नई अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीति देश के मौजूदा और नए विकसित आर्थिक ढांचे का इस्तेमाल करना चाहती है, साथ ही मौजूदा और भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से इसे रीडिज़ाइन भी कर रही है। सप्लाई चेन में रुकावटें, बढ़ते व्यापार प्रतिबंध, फिर से उभरते टैरिफ के खतरे और भू-राजनीतिक तनाव- ये सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इसे देखते हुए भारत को भरोसेमंद, लंबे समय के सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रति दृष्टिकोण वैश्विक व्यापार माहौल के साथ बदल रहा है क्योंकि रुझान बताते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षणवादी नीतियां ज्यादा आम हो रही हैं और एशिया-प्रशांत में वाणिज्य ज़्यादा क्षेत्रीय हो रहा है।

मोदी सरकार की नई रणनीति में अपने मौजूदा आर्थिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित करना और उसका इस्तेमाल करना दोनों शामिल हैं। मोदी सरकार की तरफ से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मैन्युफैक्चरिंग का देश की जीडीपी में 20% से भी कम योगदान था, जबकि सेवाओं का 50% से ज़्यादा था। इसलिए, भारत की रणनीति घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और मैन्युफैक्चरिंग में निर्यात की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है, साथ ही भारतीय सेवाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में इंटीग्रेट करने को ऑप्टिमाइज़ करना है।

मोदी सरकार के तहत भारत ने कई महत्वपूर्ण पॉलिसी बदलाव किए हैं जो पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि अंदरूनी समस्याओं को सुलझाया जा सके और बाहरी माहौल में होने वाले बदलावों के हिसाब से खुद को ढाला जा सके।

मेक इन इंडिया 2.0 पहल के ट्रेड रिफॉर्म्स का मकसद 27 अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को मज़बूत करना और देश को दुनिया के लिए एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित करना है।

लंबे समय तक चलने वाले विदेशी निवेश को आकर्षित करना और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाना इस कोशिश के दो मुख्य लक्ष्य हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेश, विकास और स्थिरता के लिए बेहतरीन जगह के तौर पर देश की प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने के लिए, सरकार रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को बढ़ावा दे रही है, खास इंसेंटिव दे रही है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विस्तार कर रही है।

साल 2030 तक अपने एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत ने साल 2023 में अपनी विदेश व्यापार नीति (FTP) को फिर से डिज़ाइन किया। FTP एक लचीली और गतिशील रणनीति है जो एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है, प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करता है, व्यापार के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। इसका मकसद एक ऐसा रिस्पॉन्सिव और अनुकूलनीय ढांचा बनाना है जिसे तय पॉलिसी चक्रों का इंतजार किए बिना बदला जा सके। इस व्यापार रणनीति के अनुरूप, मोदी सरकार के 2026 के केंद्रीय बजट में भारत को एक वैश्विक उत्पादन और सोर्सिंग बेस के रूप में स्थापित करने के लिए नई पहलें शामिल थीं, जो मुख्य रूप से रक्षात्मक व्यापार रुख से हटकर अधिक आक्रामक, दूरदर्शी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही हैं।

भारत की बदलती व्यापार नीतियों का लक्ष्य सिर्फ एक्सपोर्ट और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अर्थव्यवस्था को वैश्विक नेतृत्व के लिए फिर से स्थापित करना है। व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों और सरल टैरिफ प्रणालियों के साथ उत्पादों और सेवाओं के उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। भारत हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, श्रम-गहन एक्सपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत मुक्त व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित करके साल 2032 तक .10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की नींव रख रहा है। इन सुधारों का मकसद लंबे समय में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और नौकरियां पैदा करना भी है, खासकर भारत के युवाओं के लिए।

ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की। यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका वैश्विक जीडीपी में 25% हिस्सा है, और भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक भरोसेमंद साझेदारी और अभूतपूर्व बाजार पहुंच स्थापित कर रही हैं। 99 प्रतिशत से अधिक भारतीय निर्यात को यूरोपीय संघ में तरजीही प्रवेश दिया गया है, जिससे विकास की अपार संभावनाएं खुल रही हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का मूल लक्ष्य भारत और 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच व्यापार की पूर्वानुमेयता, सामर्थ्य और सुगमता में सुधार करना है।

कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे श्रम-गहन उद्योगों में 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को FTA के तहत तरजीही पहुंच से बहुत फायदा होगा, FTA MSMEs के लिए नए अवसर खोलेगा और महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और पेशेवरों के लिए रोजगार पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक बाजार पहुंच के साथ स्नञ्ज का सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड ऑटो उदारीकरण भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के लिए दरवाजे खोलेगा और संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी क्षेत्र को बिना किसी बाजार पहुंच के सुरक्षित रखेगा।

यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक भागीदारों में से एक है, जिसमें उत्पादों और सेवाओं में द्विपक्षीय वाणिज्य समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के आयात के साथ 2024-2025 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुल 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा। साल 2024 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सेवाओं में व्यापार कुल 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक और युवा, जोशीली कामकाजी आबादी के साथ भारत इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाकर रोज़गार बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने, कई तरह के उद्योगों में मौके खोलने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

कमोडिटी और सेवाओं में ट्रेड, ट्रेड रेमेडीज़, कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन जैसे पारंपरिक सेक्टर के अलावा, भारत-E ट्रेड पैक्ट में SMEs और डिजिटल ट्रेड जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा, E सदस्य देशों में जहां पारंपरिक मेडिकल तरीकों को रेगुलेट नहीं किया जाता है, वहां भारत ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर्स को अपने टाइटल के तहत काम करने का अधिकार हासिल कर लिया है।

विविधीकरण और आगे का रास्ता

भारत का 22वां मुक्त व्यापार भागीदार श्च है।

भारत ने साल 2025 में न्यूजीलैंड के साथ एक व्यापार समझौते के पूरा होने की घोषणा की और ओमान और यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। E व्यापार समझौता, K के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता और FETA अनिवार्य रूप से भारतीय कंपनियों, निर्यातकों और उद्यमियों को पूरे यूरोपीय बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार सौदा अब तक का सबसे अच्छा सौदा होगा और भारतीय कंपनियों को बहुत मदद करेगा।

यह देखते हुए कि भारत का माल निर्यात कुछ ही महत्वपूर्ण देशों और वस्तुओं पर केंद्रित है और इन समूहों के बाहर की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, विविधीकरण आवश्यक है।

वर्ष 2024 में भारत के माल निर्यात का 39न्न अमेरिका और EU को गया, जो इसके दो सबसे बड़े निर्यात गंतव्य हैं। ये बाजार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भी मुख्य गंतव्य हैं और भारत के सेवा निर्यात के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं।

भारत एक ऐसा भविष्य का व्यापारिक माहौल बना रहा है जो अपने मजबूत स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ एकीकृत करने और राष्ट्र के अधिक वैश्विक आर्थिक एकीकरण की ओर बढ़ने के साथ-साथ कई लॉजिस्टिकल और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को कुशलता से संबोधित करने का प्रयास करता है। भारत के कई उद्योग, जो समय के साथ फले-फूले हैं, देश के मजबूत स्थानीय वाणिज्यिक माहौल में परिलक्षित होते हैं। इन उद्योगों में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग मशीनरी, लोहा और इस्पात शामिल हैं।731.2 मिलियन श्रमिकों के साथ भारत के पास एक ऐसा श्रम बल है जो चीन के करीब है और दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश युग में प्रवेश कर रहा है, जबकि कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती उम्र के कार्यबल की सिल्वर सुनामी का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो महत्वपूर्ण कौशल के समूह को कम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2025 और 2030 के बीच भारत की जनसंख्या में औसमिक वार्षिक दर से 0.8न्न की वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत के पास एक बड़ा लेकिन अप्रयुक्त श्रमबल है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार चर्चाओं में और अधिक क्षेत्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के प्रयासों में एक प्रतिस्पर्धी बढ़त देता है।

कुल मिलाकर, भारत की व्यापार नीति अभी भी बदल रही है, जो बढ़ती अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के महत्व के बीच संतुलन बना रही है। वैश्विकरण अपनाने से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फायदों से आर्थिक विकास बढ़ाकर और जीवन स्तर को ऊपर उठाकर काफी बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा, यह रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे कुल मिलाकर प्रभावशीलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

अमेरिकी टैरिफ कटौती में भारत से ज्यादा अमेरिका का हित

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में कई बार फैसले तत्काल फायदे से अधिक दूरगामी मजबूरियों का नतीजा होते हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना भी ऐसा ही एक निर्णय है, जिसे सतही तौर पर भारत के पक्ष में बड़ी जीत माना जा रहा है, किंतु गहराई से देखने पर यह कदम अमेरिका के अपने घरेलू हितों, खासकर महंगाई से जूझते आम अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत देने की मजबूरी का परिणाम अधिक नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का धैर्य, संतुलित कूटनीति और दीर्घकालिक सोच आखिरकार रंग लाती दिखाई दी है।

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने टैरिफ को एक राजनीतिक और रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और यहां तक कि भारत जैसे मित्र देशों पर भी भारी शुल्क लगाए गए। उद्देश्य इसके पीछे जो दिखा, वह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आयात को महंगा कर अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना रहा लेकिन व्यवहार में इसका असर उल्टा पड़ा। ऊंचे टैरिफ का सीधा बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा, महंगाई बढ़ी और सप्लाई चेन में अस्थिरता आई। आज जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था महंगाई के दबाव से कराह रही है, तब ट्रंप प्रशासन को यह समझमें आया कि टैरिफ की यह आक्रामक नीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा कि यहीं से भारत के प्रति अमेरिकी रुख में बदलाव होता हुआ दिखता है। भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करना आज भारत से अधिक अमेरिकी बाजार में कीमतों को काबू में रखने की एक व्यावहारिक कोशिश भी है। भारत से आने वाले टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, केमिकल और आईटी सेवाएं अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए अहम हैं। इन पर ऊंचा शुल्क अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ाता था, जिसका असर सीधे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पड़ता था। ऐसे में टैरिफ कटौती अमेरिका के लिए अपनी ही अर्थव्यवस्था को राहत देने का रास्ता बन गई।

वैश्विक तुलना करें तो भारत की स्थिति अब कहीं अधिक मजबूत नजर आती है। नए टैरिफ ढांचे में भारत पर 18 प्रतिशत शुल्क है, जबकि इंडोनेशिया पर 19, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 और चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लागू है। यह अंतर वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में बड़ा बदलाव है। अमेरिकी आयातक स्वाभाविक रूप से कम शुल्क वाले देशों से खरीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस दौड़ में भारत अब अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से आगे खड़ा दिखेगा। यह बढ़त भारत की मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात रणनीति के लिए बेहद अहम कही जा सकती है।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा और भू-राजनीति से जुड़ा है। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाया जाना इस बात का संकेत है कि अमेरिका व्यापार नीति को रणनीतिक लक्ष्यों से जोड़कर देख रहा है। अमेरिका के लिए यह फैसला रूस पर दबाव बढ़ाने और अपने सहयोगियों को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा है, जबकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता में रखते हुए संतुलित रुख अपनाया हुआ है।

यहां भारत का धैर्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूस-युक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद बढ़ाई, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतें और घरेलू अर्थव्यवस्था इसकी मांग करती थीं। पश्चिमी देशों के कई दबाव आते रहे, बावजूद भारत ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा संबंधी फैसले राष्ट्रीय हित और बाजार परिस्थितियों के आधार पर होंगे। यही धैर्य और आत्मविश्वास अंततः भारत के पक्ष में अब आता हुआ दिखता है। पहले भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और अब अमेरिका का खुद यह स्वीकार करना कि टैरिफ नीति में लचीलापन जरूरी है, आज यह साबित करता है कि जल्दबाजी के बजाय भारत द्वारा संतुलित कूटनीति उसके पक्ष में कितनी प्रभावी रही है।

इस व्यापार समझौते का सीधा प्रतिबिंब भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला, जहां समझौते के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जबरदस्त उछाल दिखा है। ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और मेटल जैसे सेक्टर्स में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यह बाजार प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि निवेशक इस फैसले को भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक वृद्धि के लिए सकारात्मक मान रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता चालू खाते के घाटे को कम करने, रुपये को स्थिर रखने और बाहरी झटकों के प्रति भारत की संवेदनशीलता घटाने में मदद करेगा। बेहतर बाजार पहुंच और टैरिफ में स्थिरता से निर्यात बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश आएगा और एफडीआई को मजबूती मिलेगी। खासकर वे सेक्टर, जिनकी अमेरिकी बाजार में मजबूत मौजूदगी है, उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।इसके साथ ही यहां जो अभी सिर्फ भारत के हित में निर्णय को मान रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ये निर्णय भारत से ज्यादा अमेरिका के अपने हित में है, क्योंकि अमेरिका इस समय महंगाई और आर्थिक दबाव से गुजर रहा है, उसमें सस्ते और भरोसेमंद आयात के लिए भारत एक बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता है। टैरिफ घटाकर अमेरिका ने अपने उपभोक्ताओं को राहत दी है, वो सप्लाई चेन को भी स्थिर करना चाह रहा है और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत ने फिर दिखाया सामर्थ्य

-मृत्युंजय दीक्षित

भारत और अमेरिका के मध्य अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुआ टैरिफ वॉर अब समझौते के साथ समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार में उछल आया और निवेशकों के चेहरे खिल उठे। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती दिखी।

यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते के बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका दबाव में आ गया है और उसे भारत की व्यापार चिंताओं का सम्मान करना ही पड़ेगा और अंतत- ऐसा हुआ भी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की। वह सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के शक्तिशाली नेता हैं। हमने एक नहीं कई मुद्दों पर बात की जिसमें व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना भी शामिल था। मोदी के लिए दोस्ती और उनके सम्मान के चलते और उनकी मांग पर तत्काल प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25 से घटाकर 18 प्रतिशत कर रहा है।

जैसे ही सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया, वैसे ही भारत में भी हलचल तीव्र हो गई। एनडीए संसदीय दल की बैठक में अमेरिका के साथ हो रहे समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने बहुत समय तक धैर्य रखा, जिसका परिणाम हम सभी के सामने है। अमेरिका की ओर से की गई इस घोषणा से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

भारत सर्वाधिक लाभ में: भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उसका सर्वाधिक लाभ भारत को मिलने जा रहा है।टैरिफ को लेकर ट्रंप की घोषणा के बाद भारत इस मामले में पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अधिक लाभ में आ गया है।

चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत पर अब कम टैरिफ है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम भारत से अधिक टैरिफ वाले देश बन चुके हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश और वियतनाम पर 20, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लगा हुआ है। समाचार यह भी है कि अब भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा जा रहा है कि इसे संभावित रूप से शून्य तक ले जाया जा सकता है। यह भारत की वर्तमान व्यापार नीति में बाजार पहुंच के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। जैसे ही भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलेगा कई अमेरिकी वस्तुएं भारतीय उपभोक्ताओं के लिए काफी सस्ती हो जाएंगी।

भारतीय बाजार में लैपटॉप, गैजेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कीमतें कम हो सकती हैं। घरेलू उपकरणों की पहुंच आसान हो जाएगी।निर्यात के मोर्चे पर भी भारत को बहुत लाभ होने जा रहा है। अमेरिका से टैरिफ कम हो जाने के बाद हमारे टैक्सटाइल, आभूषण और रत्न निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन सेक्टर्स के अलावा भारत का चमड़ा और फुटवियर उद्योग अमेरिका को हर वर्ष 1.18 अरब, केमिकल उद्योग 2.34 अरब और इलेक्ट्रिक और मशीनरी उद्योग 9 अरब डॉलर का निर्यात करता है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार अगले कुछ वर्षों में 500 अरब डॉलर की ओर 5 गुना गति से बढ़ेगा और नए व्यापार समझौते से भारी आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। अमेरिका के साथ डील फाइनल हो जाने के कारण अब एक नई सप्लाई चेन मिल गई है जिसका लाभ भी भारत को मिलेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो सकती है। टैरिफ कटौती से भारत की आर्थिक वृद्धि निवेश, वातावरण और वाह्य संतुलन को समर्थन मिलेगा। गोल्डमैन एक्स का मानना है कि अगर यह टैरिफ लागू रहता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ होगा। अब ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता कम हो जाएगी। उद्योग जगत इसे भरोसा बढ़ाने वाला कदम मान रहा है और एफआईआई की वापसी से बाजारों में सकारात्मक वातावरण बनने की संभावना बताई जा रही है।

भारत और अमेरिका के मध्य हुआ समझौता इंगित करता है कि अब पूरी दुनिया भारत में व्यापार के माध्यम से निवेश के नए अवसर खोज रही है। यह समझौता न सिर्फ भारत की विकास आकांक्षाओं को गति देगा बल्कि देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य को भी मजबूती देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर है और यह डील विकास को अतिरिक्त गति देगी। यह कदम भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में भरोसा बढ़ाने वाला है और विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप दिख रहा है। इस समझौते के लागू हो जाने के बाद अब निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सामने आयेंगे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डोमाराजू नॉर्वे चेस 2026 में खेलेंगे

एजेंसी

स्टावेंगर (नॉर्वे)। मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डोमाराजू नॉर्वे चेस 2026 में हिस्सा लेंगे। दुनिया के सबसे मजबूत शतरंज टूर्नामेंटों में गिने जाने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में गुकेश एक बार फिर इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व चैंपियन के रूप में उतरेंगे।गुकेश ने नॉर्वे चेस में वापसी को लेकर खुशी जाहिर करते हुए एक आधिकारिक बयान में कहा, 'नॉर्वे चेस में दोबारा खेलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यहां हमेशा की तरह मजबूत खिलाड़ी होते हैं और मैं सभी रोमांचक मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ' साल 2024 में गुकेश ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद तत्कालीन विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर महज 18 वर्ष की उम्र में विश्व खिताब अपने नाम किया था। उनके करियर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हैं, जिनमें 2750 रेटिंग अंक पार करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनना और 12 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर बनने का रिकॉर्ड शामिल है, जो शतरंज इतिहास में तीसरा सबसे कम उम्र का कारनामा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की हालिया सफलता में भी गुकेश की अहम भूमिका रही है। उन्होंने 2022 शतरंज ओलंपियाड में बोर्ड नंबर एक पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2024 ओलंपियाड में उन्होंने टीम गोल्ड के साथ-साथ बोर्ड एक पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया।

ओम्बुड्समैन के आदेश के बाद अमरनाथ बने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष

हैदराबाद (तेलंगाना)। ओम्बुड्समैन के आधिकारिक आदेशों के बाद अमरनाथ को हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमरनाथ 2023 में हुए एचसीए चुनाव में जगनमोहन राव से मात्र एक वोट से हारकर उपविजेता रहे थे। बाद में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोपों के चलते जगनमोहन राव की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अमरनाथ की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी का रास्ता साफ हुआ। इससे पहले अक्टूबर में तेलंगाना क्रिकेट संघ (टीसीए) ने हैदराबाद में जिला समितियों और गवर्निंग काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कर एचसीए को पूरी तरह निलंबित करने की मांग की थी। टीसीए ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से अपील की थी कि वह बीसीसीआई संविधान और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अनुरूप टीसीए को तेलंगाना राज्य का पूर्ण सदस्य क्रिकेट निकाय मानते हुए राज्य में क्रिकेट प्रशासन का पुनर्गठन करे। टीसीए ने एचसीए पर अवैध रूप से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि संघ बिना संवैधानिक अनुपालन, प्रशासनिक कोरम और जिला स्तर के प्रतिनिधित्व के 'वेंटिलेटर सपोर्ट' पर चल रहा है।

वर्ल्ड रेसलिंग ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया घोषित की

कोर्सिएर-सुर-वेवे (स्विट्ज़रलैंड)। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने सोमवार को लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 (एलए) के लिए कुश्ती की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई प्रणाली और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए कोटा वितरण की घोषणा की। एलए 2028 से प्रत्येक भार वर्ग में कुल 16 पहलवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये स्थान चार अलग-अलग माध्यमों से भरे जाएंगे–विश्व चैंपियनशिप, महाद्वीपीय क्वालिफायर, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर और यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग। क्वालिफिकेशन का पहला चरण अगले वर्ष होने वाली विश्व चैंपियनशिप से शुरू होगा, जिसमें कुल 72 ओलंपिक कोटा दिए जाएंगे। 18 ओलंपिक भार वर्गों में स्वर्ण, रजत और दो कांस्य पदक विजेता अपने-अपने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) के लिए एलए 2028 का टिकट पक्का करेंगे। पहले चरण में क्वालिफाई नहीं कर पाने वाले पहलवानों में से यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग में शीर्ष तीन स्थान पर रहने वाले देशों को एक-एक कोटा दिया जाएगा। यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग में एलए 2028 से पहले आयोजित सात प्रमुख प्रतियोगिताओं के परिणाम शामिल होंगे, जिनमें 2027 सीनियर महाद्वीपीय चैंपियनशिप, 2027 रैंकिंग सीरीज़ (तीन इवेंट), 2027 सीनियर विश्व चैंपियनशिप, 2028 रैंकिंग सीरीज़ (एक इवेंट) और 2028 सीनियर महाद्वीपीय चैंपियनशिप शामिल हैं। महाद्वीपीय परिणामों में से केवल दो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को ही गिना जाएगा।

फीफा अध्यक्ष इन्फैंटिनो ने कहा-रूस पर प्रतिबंध बेकार, 2026 में विश्व कप का बहिष्कार नहीं

लंदन। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने रूस पर लगे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतिबंध को समाप्त करने का समर्थन करते हुए कहा है कि चार साल का यह बैन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने इसे 'निरर्थक' करार देते हुए खासतौर पर रूस की युवा टीमों की बहाली की पैरवी की। स्काई स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में इन्फैंटिनो ने कहा, 'हमें रूस की बहाली पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रतिबंध ने कुछ हासिल नहीं किया है। इससे सिर्फ निराशा और नफरत बढ़ी है। अगर रूस के लड़के-लड़कियों को यूरोप के दूसरे हिस्सों में फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा, तो यह मददगार होगा। ' यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद फरवरी, 2022 में फीफा ने रूस को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया था। इसके चलते रूस 2022 कतर विश्व कप से बाहर हुआ और अमेरिका, कनाडा व मेक्सिको में होने वाले 2026 विश्व कप की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सका।

मुख्यमंत्री साय ने 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया उद्घाटन

एजेंसी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ राज्य व्हॉलीबॉल एसोशिएशन द्वारा 3 फरवरी से 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है।

चैंपियनशिप में भारत के लिए खेल चुके कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। रेलवे, सर्विसेस और इंडियन यूनिवर्सिटी सहित कई राज्यों की टीमें इसमें भागीदारी कर रही हैं। पुरुष वर्ग में 10 टीमें और महिला वर्ग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने फेडरेशन कप के उद्घाटन के बाद इंडोर स्टेडियम में रुककर तमिलनाडू और सर्विसेस के

बीच हुए उद्घाटन मैच को पूरा देखा। वे कांटे के मुकाबले वाले इस मैच के समाप्त होने के बाद ही स्टेडियम से निकले। विधायक सुनील सोनी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 37वीं फेडरेशन कप व्हॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ की धरती पर मैं देशभर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। व्हॉलीबॉल हमें टीमवर्क, सहयोग और समन्वय सिखाता है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने इसमें प्रदेश का काफी नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा और कौशल का पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर सके, इसके लिए जरूरी अधोसंरचना और प्रशिक्षण पर हम लगातार जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई वर्षों से बंद राज्य खेल अंलकरण सम्मान को हमने पुनः प्रारंभ किया है। ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ी की भागीदारी पर शासन की ओर से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ , रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर एक करोड़ दिए जाएंगे।

जिला रैंकिंग टूर्नामेंट : पुरुष वर्ग में विख्यात कात्याल और महिला वर्ग में कनिष्का कपूर रहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

एजेंसी

मुरादाबाद। नेक्स्टजेन स्पिनर टेबल टेनिस एकेडमी द्वारा आयोजित प्रथम जिला रैंकिंग टूर्नामेंट का समापन हुआ। नेक्स्टजेन स्पिनर टेबल टेनिस एकेडमी द्वारा मुरादाबाद में आयोजित प्रथम जिला रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद जिले के लगभग 60-70 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विख्यात कात्याल और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कनिष्का कपूर रही। प्रतियोगिता में अंडर-11 से लेकर मेन्स और वुमेन्स श्रेणी तक के विभिन्न रोमांचक मुकाबले खेले गए। टूर्नामेंट के दौरान विख्यात कात्याल और कनिष्का कपूर का दबदबा रहा, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खिताब अपने नाम किए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक अनिल अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथियों में, एसपी सिन्हा, सीए राकेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, योगेंद्र गौतम जिला सचिव रहे। कार्यक्रम का मानसी तलवार ने खूबसूरत अंदाज में किया। इस टूर्नामेंट की मेजबानी नेशनल खिलाड़ी कुणाल अरोड़ा द्वारा किया गया।

पलवल में 40वीं हरियाणा राज्य महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ

एजेंसी

पलवल। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खेल विभाग पलवल एवं जिला तीरंदाजी संघ पलवल के संयुक्त तत्वाधान में सर दीनबंधु छोटू राम स्टेडियम, घुघेरा (पलवल) में आयोजित 40वीं हरियाणा राज्य महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अर्जुन अवार्डी एवं डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग हरियाणा राम मेहर, सचिव तीरंदाजी संघ हरियाणा राम निवास हुड्डा तथा आर्चरी कोच खेल विभाग पलवल दीपक कुमार भी उपस्थित रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पलवल में पहली बार राज्य स्तरीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता प्रदेश की बेटियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करेगी, जिससे उत्कृष्ट खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक

पहुंचकर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करेंगी।खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और देश का युवा यदि लक्ष्य निर्धारित कर ले, तो उसे प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास करता है। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर गौरव गौतम ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगी। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी, तीरंदाजी संघ के पदाधिकारी, कोच, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

स्मिथ ने पीएसएल फ्रेंचाइज़ी सियालकोट स्टैलियनज़ के साथ किया करार, 2028 ओलंपिक का सपना अब भी जिंदा

एजेंसी

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्टार स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की नई फ्रेंचाइज़ी सियालकोट स्टैलियनज़ के साथ करार कर लिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम में वापसी और लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में खेलने का उनका सपना अब भी कायम है, जहां पहली बार टी20 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा।

36 वर्षीय स्मिथ ने हाल ही में एशेज सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए बिग बैश लीग (बीबीएल) में भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी की। इसके बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिल सकी। स्मिथ कई बार साफ कर चुके हैं कि उनका बड़ा लक्ष्य 2028 ओलंपिक में खेलना है। हालांकि सिडनी टेस्ट के बाद उन्होंने यह भी कहा था कि उनका भविष्य 'दिन-प्रतिदिन' का मामला है। लेकिन पीएसएल में साइन करना इस बात

का संकेत है कि उनके इरादे अभी मजबूत हैं।

ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम में फिलहाल कप्तान मिच मार्श और ऑलराउंड स्टार ट्रैविस हेड को ओपनर के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके चलते चयनकर्ताओं को इन-फॉर्म स्मिथ के लिए जगह नहीं मिल पाई।

पीएसएल में सियालकोट स्टैलियनज़ के लिए खेलना स्टीव स्मिथ के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपनी दावेदारी को और मजबूत करने का अहम मौका माना जा रहा है।

गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से रौंदकर लगातार चौथी बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स

एजेंसी

वडोदरा। दिल्ली कैपिटल्स ने बीसीए स्टेडियम में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ कैपिटल्स ने लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां 5 फरवरी को उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा। डब्ल्यूपीएल 2023 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अगले साल इस टीम ने फिर से फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इस बार आरसीबी ने बाजी मार ली। साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस के हाथों एक बार फिर खिताबी मैच गंवाना पड़ा था। वडोदरा में खेले गए एलिमिनेटर मैच में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात जायंट्स ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 168 रन बनाए। इस टीम ने 59 के स्कोर तक अपने

4 विकेट गंवा दिए थे, जहां से सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने जॉर्जिया वेयरहैम के साथ पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। वेयरहैम 25 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद मूनी ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 51 गेंदों में 6 चौकों के साथ 62 रन की नाबाद पारी खेली। इनके अलावा, काशवी गौतम ने 10 गेंदों में 3 चौकों के साथ 18 रन जुटाए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से चिनले हैनरी ने 35 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, एक विकेट मिन्नु मणि के हाथ लगा। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम को लिजेल ली और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। सलामी जोड़ी ने 7.1 ओवरों में 89 रन जोड़े। लिजेल ली 24 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि शेफाली ने 21 गेंदों में 7 चौकों के साथ 31 रन जुटाए। कैपिटल्स 92 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज ने लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 68 रन जुटाते हुए टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। जेमिमा ने 23 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 41 रन बनाए, जबकि लौरा ने 24 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ नाबाद 32 रन बनाए।

पद्मश्री श्याम लाल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में श्याम लाल कॉलेज की लगातार दूसरी जीत

एजेंसी

नई दिल्ली। मेजबान श्याम लाल कॉलेज (प्रातः) ने एमिटी यूनिवर्सिटी को 7-0 से पराजित कर 12वें पद्मश्री श्याम लाल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। विजेता टीम के लिए प्रत्यूष सिंह जग्गी और हर्ष शर्मा ने दो- दो गोल किए। नंद किशोर, भूपेंद्र और रोहित ने एक- एक गोल किया। प्रत्यूष सिंह जग्गी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अन्य मुकाबलों में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने एसएलसी एलुमनी को कांटे के संघर्ष 4-3 से मात दी। विजेता टीम के ऋतिक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए करण पाल, नकुल, सुमित और ऋतिक ने एक- एक गोल किया। एसएलसी एलुमनी के लिए शशिकांत ने दो और डी एस जग्गी ने एक गोल किया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस ने श्याम लाल बी टीम को 3-2 से मात दी। विजेता टीम के हर्ष यादव दो गोल कर

प्लेयर ऑफ द मैच बने। गुरमुख ने एक गोल किया।श्याम लाल बी टीम के लिए अतुल और आदित्य ने एक-एक गोल किया। किरोड़ी मल कॉलेज ने एमिटी को 2-1 से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पाने वाले चिराग ने विजेता टीम के दोनों गोल किए।

डेविस कप में इतिहास दोहराने की तैयारी, नीदरलैंड्स से भिड़ंत से पहले कप्तान रोहित राजपाल को टीम पर भरोसा

एजेंसी

बेंगलुरु। डेविस कप क्वालिफायर राउंड-1 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 7-8 फरवरी को होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टेनिस टीम बेंगलुरु के एस.एम. कृष्णा टेनिस स्टेडियम में जोरदार तैयारी में जुटी है। टीम के कप्तान रोहित राजपाल को भरोसा है कि यदि खिलाड़ी सही समय पर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल कर लें, तो भारत मजबूत डच टीम को चुनौती दे सकता है।

प्रशिक्षण शिविर में करन सिंह और रित्विक बोलिपल्ली ने अभ्यास शुरू कर दिया है, जबकि सुमित नागल, यूकी भांबरी और दक्षेश्वर सुरेश भी टीम से जुड़ने वाले हैं। कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म को ध्यान में

रखते हुए अभ्यास सत्रों की तीव्रता को धीरे-धीरे संतुलित कर रहा है, ताकि मुकाबले के समय खिलाड़ी अपने चरम प्रदर्शन पर हों।

भारत की मौजूदा डेविस कप रैंकिंग 33 है, जबकि नीदरलैंड्स दुनिया की शीर्ष टीमों में गिना जाता है और हाल के वर्षों में फाइनल तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके, भारतीय टीम 1996 की उस ऐतिहासिक जीत से प्रेरणा ले रही है, जब जयपुर में भारत ने पिछड़ने के बाद नीदरलैंड्स को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेश भूपति ने भी टीम का हौसला बढ़ाया है। उनका कहना है कि डेविस कप ऐसा मंच है, जहां रैंकिंग से ज्यादा जज्बा और टीम स्पिरिट मायने रखती है।

पिछले साल स्विट्ज़रलैंड पर मिली जीत ने भारतीय खेमे का आत्मविश्वास बढ़ाया है। कप्तान राजपाल का मानना है कि घरेलू दर्शकों का समर्थन भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 2-2 से बराबर है, ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

भारतीय टीम अब अंतिम दिनों में रणनीति और संयोजन पर खास ध्यान दे रही है, ताकि कोर्ट पर उतरते ही इतिहास दोहराया जा सके।

एशियन राइफल/पिस्टल चैम्पियनशिप: पिस्टल स्पर्धाओं से भारत को दमदार शुरुआत की उम्मीद

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही एशियन राइफल/पिस्टल चैम्पियनशिप के पहले प्रतिस्पर्धा दिवस पर भारत की नजरें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं पर टिकी हैं। बुधवार को इन स्पर्धाओं के पदक दांव पर होंगे और मेजबान भारतीय टीम मजबूत शुरुआत के इरादे से उतरेगी। भारतीय चुनौती की अगुवाई विश्व चैंपियन सम्राट राणा, वर्ल्ड कप फाइनल विजेता सुरुचि सिंह, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और उभरती स्टार ईशा सिंह करेंगी। इन खिलाड़ियों से पदक की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन कुल चार फाइनल खेले जाएंगे। इनमें सीनियर पुरुष और महिला वर्ग के अलावा जूनियर और यूथ पुरुष वर्ग शामिल हैं। सम्राट राणा और सुरुचि सिंह को स्वर्ण पदक का दावेदार माना जा रहा है, जबकि महिला वर्ग में मनु भाकर और ईशा सिंह से भी शीर्ष

प्रदर्शन की उम्मीद है। महिला वर्ग में हांगकांग की हो चिंग शिंग बड़ी प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही हैं। वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं और एशियन स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं। चीनी ताइपे की चेंग येन-चिंग और वियतनाम की अनुभवी थु विन्ह त्रिन्ह भी पदक की दौड़ को कड़ा बना सकती हैं। पुरुष वर्ग में भारत के सम्राट राणा के साथ वरुण तोमर और शरवन कुमार भी चुनौती पेश करेंगे। कजाकिस्तान, चीनी ताइपे और उज्बेकिस्तान के निशानेबाज़ भारतीय खिलाड़ियों के लिए कड़ी टक्कर साबित हो सकते हैं। भारत ने इस चैम्पियनशिप में 118 खिलाड़ियों का बड़ा दल उतारा है, जो सभी देशों में सबसे बड़ा है। कजाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा दल लेकर आया है। कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और वियतनाम जैसी पारंपरिक ताकतें भी मजबूत टीमों के साथ उतरी हैं। मेजबान होने के साथ-साथ हालिया अंतरराष्ट्रीय सफलताओं से उत्साहित भारतीय दल से इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में शानदार शुरुआत की उम्मीद की जा रही है।

भारत 2027 में करेगा एशियन राइफल-पिस्टल चैंपियनशिप की मेज़बानी

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में ओलंपिक खेल शूटिंग की शासी संस्था, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने घोषणा की कि नई दिल्ली ने एशियन राइफल-पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी का अधिकार हासिल कर लिया है। इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता में लॉस एंजेलिस 2028 (एलए 28) ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए आठ कोटा स्थान दांव पर होंगे। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन (एएससी) के महासचिव इंजीनियर दुआइज अलओतैबी ने 2 फरवरी को एनआरएआई अध्यक्ष कालिकेश नारायण सिंह देव को भेजे गए पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि की। यह लगातार दूसरा अवसर होगा, जब भारत राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं की इस शीर्ष महाद्वीपीय चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। इस खेल की वैश्विक शीर्ष संस्था अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (आईएसएसएफ) ने पहले ही अप्रैल, 2027 में नई दिल्ली में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन के आयोजन का अधिकार भारत को दिया है, जिसमें कुल 12 एलए 28 कोटा स्थान उपलब्ध होंगे।

खेल मंत्री डॉ. मांडविया ने 6 खेल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से देशभर में छह प्रमुख खेल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी और दो एथलीट-केंद्रित सुविधाओं का उद्घाटन किया। इन सभी परियोजनाओं पर कुल 120 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह पहल भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इन परियोजनाओं में बेंगलुरु में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उन्नयन, पटियाला में बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण, भोपाल, गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्थापना तथा भोपाल में बहुउद्देश्यीय जूडो हॉल का निर्माण शामिल है। 82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली छह आधारशिला परियोजनाएं खेलो इंडिया योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं, जिन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का सहयोग भी प्राप्त है। ये परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों–विशेषकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों–में स्थापित की जा रही हैं, ताकि संतुलित और समावेशी खेल अवसंरचना विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा डॉ. मांडविया ने एनएस एनआईएस, पटियाला में 38 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई दो एथलीट-सहायक सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। इनमें एथलीटों की पोषण आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए केंद्रीयकृत किचन एवं फूड कोर्ट-सह-डाइनिंग हॉल तथा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एवं कंडीशनिंग हॉल शामिल है। ये सुविधाएं वैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन विश्लेषण, पुनर्वास और रिकवरी में एलीट एथलीटों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

इस अवसर पर सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए और परिसंपत्ति प्रबंधन में साई की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए खेल मंत्री ने कहा, 'देशभर में कई खेल अवसंरचना परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, लेकिन साई के अंतर्गत आने वाली सुविधाएं हमारी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी हैं। इन परिसंपत्तियों का समुचित रखरखाव, प्रभावी उपयोग और जहां संभव हो, व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि सार्वजनिक निवेश दीर्घकालिक मूल्य सृजित कर सके। 'डॉ. मांडविया ने यह भी स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं की निरंतर निगरानी की जाएगी। साई स्तर पर मासिक समीक्षा और स्वयं उनके स्तर पर तिमाही समीक्षा की जाएगी, ताकि परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और एथलीटों के हित में उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।खेल क्षेत्र की व्यापक नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत खेल अवसंरचना विकास सहित भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा, 'हमें मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को साकार करना है, जिसके तहत भारत को 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में और स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल किया जाना है।' खेल मंत्री ने यह भी बताया कि खेल सामग्री निर्माण के लिए ?500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होगा।खेलों की बदलती भूमिका पर जोर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, 'आज खेल एक पेशा बन चुका है।

जियो स्टूडियोज ने सिख्या एंटरटेनमेंट में खरीदी बहुमत हिस्सेदारी

एजेंसी

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने फिल्म और कंटेंट के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सिख्या एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है। करीब 150 करोड़ रुपये के इस सौदे में नए निवेश के साथ-साथ मौजूदा हिस्सेदारी की खरीद भी शामिल है। इस डील के बाद जियो स्टूडियोज को रचनात्मक ताकत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिख्या एंटरटेनमेंट भारत की जानी-मानी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्रोडक्शन कंपनी है। इसे गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन ने स्थापित किया था। इस कंपनी ने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने भारतीय कहानियों को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। सिख्या खास इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र भारतीय प्रोडक्शन हाउस है, जिसने ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है। इसकी मशहूर फिल्मों में 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' और 'द एलीफेंट व्हिसपरर्स' शामिल हैं। वहीं 'मसान', 'सोरारई पोट्रू' और 'कटहल' जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।जियो स्टूडियोज पहले से ही बड़ी और सफल फिल्मों के निर्माण और वितरण में सक्रिय है। अब सिख्या की मजबूत कहानी कहने की कला और जियो के बड़े नेटवर्क के साथ मिलकर भारतीय फिल्मों और सीरीज को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा।

सर्राफा बाजार की कमजोरी जारी, सोना-चांदी की घटी कीमत

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में गिरावट का रुख लगातार जारी है। सोना आज 6,800 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 7,410 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 19 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक की दर्ज की गई है। सोने की कीमत में कमजोरी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,53,160 रुपये से लेकर 1,53,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,40,390 रुपये से लेकर 1,40,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,53,310 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,540 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,53,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,440 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

पेपाल में मैनेजमेंट बदलाव, बोर्ड ने एनरिक लोरेस को बनाया नया CEO और प्रेसिडेंट

सैन जोस। ऑनलाइन पेमेंट दिगज पेपाल ने कंपनी के भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने शीर्ष प्रबंधन में अहम फेरबदल किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनुभवी टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव एनरिक लोरेस को कंपनी का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वे 1 मार्च 2026 से जिम्मेदारी संभालेंगे और मौजूदा सीईओ एलेक्स क्रिस का स्थान लेंगे। कंपनी ने संक्रमण काल को सहज रखने के लिए चीफ फाइनेंशियल एवं ऑपरेटिंग ऑफिसर जेमी मिलर को अंतरिम सीईओ बनाया है। वहीं, डेविड डब्ल्यू. डोरमैन को तुरंत प्रभाव से स्वतंत्र बोर्ड चेयर की भूमिका सौंपी गई है।बोर्ड ने यह निर्णय कंपनी के प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धी माहौल और इंडस्ट्री की बदलती दिशा की समीक्षा के बाद लिया। बोर्ड का मानना है कि हाल के वर्षों में कुछ सुधार जरूर हुए, लेकिन अपेक्षित गति से बदलाव नहीं हो पाया, जिसके चलते नए नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। एनरिक लोरेस को टेक और कमर्शियल सेक्टर में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। वे पिछले करीब पांच साल से पेपाल बोर्ड से जुड़े रहे हैं और जुलाई 2024 से बोर्ड चेयर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। कंपनी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव और रणनीतिक सोच से पेपाल को डिजिटल पेमेंट बाजार में नई मजबूती मिलेगी और कंपनी अगले विकास चरण में तेजी से आगे बढ़ेगी।

जियो-ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने लॉन्च की 'पर्सनालाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज'

मुंबई। जियोब्लैकरॉक इंवेस्टमेंट एडवाइज़रस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में 'जियोब्लैकरॉक पर्सनालाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज' की शुरुआत की है। यह एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। कंपनी का दावा है कि वह भारतीयों को सिर्फ बचतकर्ता नहीं बल्कि समझदार निवेशक बनाना चाहती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक की 50:50 की जॉइंट वेंचर कंपनी है जियोब्लैकरॉक इंवेस्टमेंट एडवाइज़रस प्राइवेट लिमिटेड। इस मौके पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा एम. अंबानी ने कहा कि हर भारतीय की वित्तीय मजबूती देश को 'विकसित भारत 2047' की दिशा में आगे ले जाने के लिए जरूरी है। JioBlackRock का लक्ष्य भारत को बचतकर्ताओं के देश से आत्मविश्वासी निवेशकों के देश में बदलना है। उन्होंने बताया कि Jio की डिजिटल पहुंच और BlackRock के वैश्विक निवेश अनुभव के जरिए आम लोगों तक विश्वस्तरीय निवेश सलाह पहुंचाई जाएगी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से किसानों को नुकसान नहीं, डेयरी और कृषि क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित: पीयूष गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इससे युवाओं के लिए अवसरों का सृजन होगा। गोयल ने दावा किया कि व?यापार समझौते से भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को संरक्षण मिला है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर ताजा घोषणा के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आज यहां मीडिया के समक्ष समझौते का पूरा ब्यौरा रखा। गोयल ने कहा कि यह व्यापार समझौता वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है।उन्होंने कहा कि वे इस बारे में संसद में बोलना चाहते थे लेकिन

विपक्षी सदस्यों की तरफ से संसद में किए गए हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो पाया। भारत पर टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किए जाने पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नए घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को सबसे अच्छा सौदा बताया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंधों को दिया और जोर देकर कहा कि बातचीत के दौरान भारत का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रहा।

गोयल ने कहा, आज देशभर में हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार समझौता पक्का करने के लिए धन्यवाद दे रहा है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित सबसे आगे रखते हुए एक डील फाइनल की गई है, जो मजबूत भारत के भविष्य को ताकत देगी। इस समझौते को शानदार बताते हुए वाणिज?य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री के लिए बड़े मौके खुलेंगे।

आरबीआई की तीन दिवसीय मौद्रिक समीक्षा बैठक, रेपो रेट यथावत संभव

एजेंसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक 6 फरवरी तक चलेगी। बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा संजय मल्होत्रा 6 फरवरी को करेंगे। इस समीक्षा बैठक में रेपो रेट यथावत रहने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों ने बताया कि आरबीआई इस बार एमपीसी की बैठक में नीतिगत दर रेपो रेट यथावत रख सकता है। आरबीआई फरवरी 2025 से लेकर अब तक रेपो रेट में कुल 125 फीसदी तक की कटौती कर चुका है, जिससे नीतिगत दर रेपो रेट घटकर 5.25 फीसदी पर आ गया है।अर्थशास्त्रियों के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है। जानकारों का कहना है कि

महंगाई अब अपने निचले स्तर से दोबारा ऊपर आने लगी है, इसलिए केंद्रीय बैंक और जोखिम लेने से बचेगा। गौरतलब है कि दिसंबर, 2025 की कटौती के दौरान चौथी रेपो रेट कटौती थी, जिससे सालभर में कुल 125 फीसदी की कटौती हो गई।

भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग को मिलेगी नई गति

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और भूटान ने अपने द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली में भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योंपो जेम शेरिंग ने केंद्रीय विद्युत एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल तथा विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक से मुलाकात की। विद्युत मंत्रालय के अनुसार इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जलविद्युत सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आज की चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने पुनात्सांगचू-द्वितीय जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) से बिजली उत्पादन के व्यावसायिक अनुकूलन पर विचार-विमर्श किया। पुनात्सांगचू-द्वितीय जलविद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) के शीघ्र चालू होने पर भी जोर दिया गया। संकोश जलविद्युत

परियोजना के भविष्य के दृष्टिकोण पर भी विचार-विमर्श हुआ।इसके अलावा, भारत और भूटान 2040 तक एक मजबूत पावर ग्रिड नेटवर्क तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। चर्चा का एक अहम पहलू भूटान में सर्दियों के दौरान होने वाली बिजली की किल्लत रहा, जिसके समाधान के लिए सप्लाई अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति बनी। मंत्रियों ने इस सहयोग को दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक बताया। उल्लेखनीय है कि भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग की शुरुआत 1961 में हुई, जिसके बाद 2006 में जलविद्युत सहयोग पर एक समझौता हुआ।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक कदम: खंडेलवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। भाजपा के सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता को विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया है। खंडेलवाल ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देगा, भारत में निवेश को प्रोत्साहित करेगा तथा विशेष रूप से एमएसएमई, स्टार्टअप्स और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करेगा। कैट महामंत्री ने कहा कि यह मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों को मजबूती प्रदान करते हुए भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजारों तक व्यापक पहुंच दिलाएगा और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि इस

व्यापार समझौते से विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, कृषि उत्पाद, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। भारतीय निर्यातकों, व्यापारियों और उद्यमियों को व्यापार अवरोधों में कमी, बेहतर बाजार पहुँच और प्रौद्योगिकी सहयोग का सीधा लाभ प्राप्त होगा।

खंडेलवाल ने आगे कहा कि इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पक्ष नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और सतत आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भारत-अमेरिका व्यापार समझौता केवल एक व्यावसायिक समझौता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक साझेदारी है, जो भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा को तेज करेगी और देश को वैश्विक विनिर्माण एवं व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

देश में एकीकृत और स्वदेशी कंटेनर परिस्थितियंत्र बनाने के लिए हुआ समझौता, सर्बानंद सोनोवाल और अश्विनी वैष्णव ने बताया अहम

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में एकीकृत और स्वदेशी कंटेनर परिस्थितियंत्र बनाने के लिए भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (बीसीएसएल) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने समझौता भारतीय शिपिंग निगम (एससीआई), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण, चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएमएफसीएल) के साथ किया। इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रहे। समारोह में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी मौजूद थे। मंत्रालय ने यह समझौता केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम (सीएमएएस) को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में अहम द्य है। साथ ही वीओ चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण (तूतीकोरिन) में आउटर हार्बर परियोजना के वित्तपोषण के

लिए एक अलग त्रिपक्षीय एमओयू भी किया गया। समझौता वीओसी पोर्ट प्राधिकरण, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) और एसएमएफसीएल के बीच हुआ है। इसके तहत सागरमाला कार्यक्रम और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत पत्तन क्षमता विस्तार के लिए अधिकतम 15,000 करोड़ रुपये तक की संयुक्त वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। यह फंडिंग मुख्य रूप से ब्रेकवाटर निर्माण और संबंधित ऑनशोर-ऑफशोर सुविधाओं के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि बीसीएसएल और आउटर हार्बर परियोजना से जुड़े ये दोनों समझौते राष्ट्रीय शिपिंग क्षमता को मजबूत करने, पत्तन अवसंरचना के विस्तार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में रणनीतिक कदम हैं। ये पहलें समुद्री अमृत काल 2047 के विजन के अनुरूप भारत की वैश्विक समुद्री उपस्थिति को सुदृढ़ करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह एक लंबे समय से लंबित दृष्टि का साकार रूप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में परियोजनाओं को तेजी और दक्षता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉनकोर के सहयोग से विकसित की जा रही यह नई कंटेनर शिपिंग लाइन देश में विश्वस्तरीय कंटेनर इकोसिस्टम के निर्माण में सहायक होगी। राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि ये दोनों एमओयू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाते हैं, जिनके कारण भारत न केवल भूमि पर बल्कि समुद्र में भी एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

आयकर विभाग की बाबा ग्रुप और चावल व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी समाप्त

एजेंसी

रांची। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा की बाबा ग्रुप और चावल व्यापारियों के ठिकानों पर की गयी छापेमारी मंगलवार की देर रात समाप्त हो गयी। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 100 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति जब्त की गयी। इसमें 50 करोड़ रुपये का चावल का स्टॉक, 15 करोड़ रुपये के जेवरीत, पांच करोड़ रुपये नकद और संपत्ति के मूल्य में 25 करोड़ रुपये का अंतर शामिल है। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा (रांची) ने 29 जनवरी को बाबा एग्रो, बाबा फुड प्रोसेसिंग और बाबा ग्रुप से जुड़े आढ़तियों (कमीशन एजेंट) के 45 ठिकानों पर झारखंड और बिहार से ठिकानों छापा मारा था। वर्ष 2026 में आयकर विभाग की और से की जाने वाली यह पहली छापेमारी है। यह कार्रवाई व्यापारियों की ओर से अपनी वास्तविक आमदनी छिपा कर टैक्स चोरी करने के मामले में की गयी थी।

केंद्रीय बजट में प्रोविडेंट फंड के लिए आयकर नियमों में बदलाव का ईपीएफओ ने किया स्वागत

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों को नियंत्रित करने वाले आयकर ढांचे के युक्तिकरण का स्वागत किया है। ईपीएफओ ने कहा कि इस कदम से बहुत ज़रूरी स्पष्टता आएगी, मुकदमेबाजी कम होगी और हितधारकों को बेहतर सेवा मिलेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि केंद्रीय बजट 2026-2027 में आयकर व्यवस्था के युक्तिकरण से भविष्य निधि अधिनियम के साथ तालमेल और सामंजस्य स्थापित करके इसके हितधारकों के हितों की पूर्ति में अत?यधिक मदद मिलेगी। अब यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईपीएफ छूट कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध

प्रावधान अधिनियम, 1952 द्वारा शासित है। निवेश मानदंड अब ईपीएफ निवेश मानदंडों के अनुरूप कर दिए गए हैं और नियोक्ता के अंशदान की सीमा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुरूप निधि को नियंत्रित करने वाले आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के वैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों के साथ संयोजित किया है। मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026-2027 ने मान्यता प्राप्त भविष्य आयकर अधिनियम, 2025 के तहत मान्यता केवल उन्हीं भविष्य निधियों को प्राप्त होगी, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त की है।

निवेश संबंधी नियम लागू ईपीएफ ढांचे और अधीनस्थ कानूनों के तहत विनियमित होते रहेंगे। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को 50 फीसदी तक सीमित करने वाली कठोर वैधानिक सीमा को हटा दिया गया है।

नियोक्ता का योगदान

नियोक्ता का अंशदान 7.5 लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा के अंतर्गत होगा। इस मौद्रिक सीमा के पार होने पर अंशदान पर अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारत की वृद्धि को मिलेगी गति : उद्योग जगत

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष उद्यमियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को गति प्रदान देगा। व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए महिंद्रा समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) अनीश शाह ने इसे ''द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम'' बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत वृद्धि पथ पर होने के साथ यह सौदा भारत की वृद्धि महत्वाकांक्षाओं को सार्थक गति प्रदान करेगा। अमेरिकी राष?ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बड़ा ऐलान भी किया है, जिसके तहत भारत पर लागू टैरिफ घटाकर तत्काल 18 फीसदी करने की घोषणा की है। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि कम शुल्क से इन दो महान देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और निवेश तथा सहयोग के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने, विनिर्माण के अवसरों को खोलने और अमेरिका तथा भारत में दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने भी कहा कि भारतीय सामानों पर अमेरिकी जवाबी शुल्क को घटाकर 18 फीसदी करना एक सकारात्मक कदम है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है और दीर्घकालिक द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में विश्वास पैदा करता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में, व्यापार में खुलापन भारतीय उद्योग को विस्तार करने, नवाचार करने और नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। इसी तरह महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, 'इससे संभलकर आगे बढ़ने के लाभों का पता चलता है। जब शोर थम जाएगा, तो दो स्वाभाविक साझेदार साथ आएंगे।' आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने 'एक्स' पर लिखा, 'पहले यूरोपीय संघ के साथ 'मदर ऑफ ऑल डील्स' और अब अमेरिका के साथ 'फादर ऑफ ऑल डील्स' से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। '

अडानी पोर्ट्स को तीसरी तिमाही में 3,043 करोड़ रुपये का मुनाफा

एजेंसी

अहमदाबाद। अडानी समूह की मुख्य कंपनी अडानी पोर्ट्स को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में समेकित आधार पर 3,043 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। कंपनी के निदेशक मंडल की मंगलवार को हुई बैठक में वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की गयी। इसमें बताया गया है कि तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 3,043 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान उसका राजस्व 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9,705 करोड़ रुपये पर रहा। कंपनी ने बताया कि घरेलू बंदरगाह कारोबार से उसे 6,701 करोड़ रुपये और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कारोबार से 1,067 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें क्रमशः 15 प्रतशत और 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लॉजिस्टिक्स कारोबार से प्राप्त राजस्व 62 फीसदी बढ़कर 1,121 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। घरेलू बंदरगाह कारोबार में रिकॉर्ड 4,877 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज किया गया है। देश के कंटेनर बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 45.8 फीसदी रही। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कारोबार का राजस्व पहली बार 1,000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। कंपनी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में 38,000 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य तय किया है। साथ ही परिचालन लाभ 22,800 करोड़ रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

अमेरिकी व्यापार समझौते की घोषणा से झूमा शेयर बाजार, निवेशकों ने कमाये 12.06 लाख करोड़ रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के ऐलान की वजह से घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। आज के कारोबार की शुरुआत जोरदार उछाल के साथ हुई थी। दिन के कारोबार में मुनाफा वसूली होने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट भी आई। इसके बावजूद ये दोनों सूचकांक जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 2.54 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी ने 2.55 प्रतिशत की उछाल के साथ आज के कारोबार का अंत किया।आज दिनभर के कारोबार के दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। निफ्टी का बैंकिंग इंडेक्स 2.43 प्रतिशत, आईटी इंडेक्स 1.41 प्रतिशत, ऑटोमोबाइल इंडेक्स 2.81 प्रतिशत, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 3.71 प्रतिशत, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 2.60 प्रतिशत, एफएमसीजी इंडेक्स 0.73 प्रतिशत, हेल्थकेयर इंडेक्स 2.83 प्रतिशत, मेटल इंडेक्स 2.85 प्रतिशत, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.77 प्रतिशत, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स 1.82 प्रतिशत और टेक इंडेक्स 1.52 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 2.79 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 2.91 प्रतिशत की मजबूती के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 467.09 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 455.03 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 12.06 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,422 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 3,299 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 989 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 134 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,941 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 2,494 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान और 447 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 28 शेयर बढ़त के साथ और 2 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 47 शेयर हरे निशान में और 3 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 3,656.74 अंक की जोरदार छलांग लगा कर 85,323.20 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारी के सपोर्ट से पहले 15 मिनट में ही ये सूचकांक उछल कर 4,205.27 अंक की जबरदस्त तेजी के साथ 85,871.73 अंक के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई, जिसकी वजह से अगले 1 घंटे के कारोबार में सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 2,370 अंक से अधिक गिर कर 83,501.22 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद खरीदारों ने एक बार फिर लिवाली का जोर बनाया, जिसकी वजह से सेंसेक्स 2,072.67 अंक की मजबूती के साथ 83,739.13 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह एनएसई के निफ्टी ने आज 1,219.65 अंक उछल कर 26,308.05 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही खरीदारी के सपोर्ट से थोड़ी ही देर में ये सूचकांक उछल कर 1,252.80 अंक की मजबूती के साथ 26,341.20 अंक के स्तर तक पहुंच गया।

महिलाओं को लेकर जमात की भेदभावपूर्ण सोच पर सवाल, राजनीति में उसकी भूमिका पर छिड़ी बहस

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकास के लिए यह ज़रूरी है कि नागरिक यह सवाल उठाएं कि महिलाओं के प्रति प्रतिगामी सोच रखने वाली जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टर राजनीतिक पार्टी को मौजूदा संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत पंजीकृत रहने और सक्रिय राजनीति करने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि जब तक इन बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, तब तक ऐसी पार्टी को देश की शासन जिम्मेदारी सौंपना गैर-जिम्मेदाराना होगा। बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम आलो में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, स्वतंत्रता की उद्घोषणा, संविधान की प्रस्तावना में निहित मानव गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता और संविधान का अनुच्छेद 28 धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक-आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके बावजूद, जमात अपने संविधान और व्यवहार दोनों के जरिए मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती दिखती है, जिससे वे व्यवहारिक रूप से द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के प्रति जमात की नकारात्मक सोच उसके अमीर (प्रमुख) के हालिया बयानों में भी साफ झलकती है। महिलाओं के काम के घंटे केवल पांच घंटे तक सीमित रखने की उनकी टिप्पणी और उससे जुड़ी बातें इस मानसिकता को दर्शाती हैं कि महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाए।

विदेश मंत्री जयशंकर ने वाशिंगटन में अपने समकक्ष मार्को रुबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की

वाशिंगटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, जिसमें भारत-अमेरिका रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'आज दोपहर अमेरिकी सीनेटर रूबियो से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी द्विपक्षीय सहयोग एजेंडा व क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के जिन पहलुओं पर चर्चा हुई, उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल थे। अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मैकेनिज्म की जल्द मीटिंग्स पर सहमति बनी।' विदेश विभाग के एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण पर द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने पर चर्चा की। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो भारत-अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है।

चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक हिंसा, 11 की मौत, 616 घायल

ढाका। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आगामी 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले देशभर में राजनीतिक हिंसा में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी महीने में हिंसा से जुड़ी घटनाओं में दिसंबर 2025 की तुलना में भारी इजाफा हुआ है। यह जानकारी ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन के हवाले से स्थानीय मीडिया ने दी। मानवाधिकार संगठन आइन ओ सालिश केंद्र (एएसके) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में राजनीतिक हिंसा की 75 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 616 लोग घायल हुए और 11 लोगों की मौत हो गई। इसके मुकाबले दिसंबर 2025 में 18 घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें 268 लोग घायल और चार की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 जनवरी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और प्रचार अभियान शुरू होने के बाद हिंसक झड़पों में और तेजी आई। एएसके के अनुसार, 21 से 31 जनवरी के बीच 49 झड़पें हुईं, जिनमें चार लोगों की मौत और 414 लोग घायल हुए। इससे साफ है कि मतदान की तारीख नजदीक आते ही हिंसा बढ़ती जा रही है।

अमेरिका के साथ तनातनी के बीच ईरान का दावा- सेना का ड्रोन समुद्र में मिशन पूरा करके लौटा

तेहरान। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सेना का एक ड्रोन समुद्र में एक मिशन पूरा करके लौटा है। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान की सेना का एक ड्रोन अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक 'निगरानी मिशन' पर था। यह दावा अमेरिकी सेना के उस बयान के कुछ समय बाद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने एक ईरानी विमान को मार गिराया है, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत करीब आ गया था। फार्स न्यूज एजेंसी ने बिना नाम लिए सूत्रों के हवाले से बताया कि ड्रोन ने ईरान के आसपास के इलाकों में मिलिट्री गतिविधियों पर सफलतापूर्वक नजर रखी और रियल टाइम में डेटा ग्राउंड बेस को भेजा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि रिपोर्ट में ऐसे मिशन को क्षेत्र की पूरी निगरानी के लिए जरूरी बताया गया है।

ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान का अपने एक ड्रोन से संपर्क टूट गया है, जिसके कारण की जांच की जा रही है और पता चलने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

ग्रीस में कोस्ट गार्ड के जहाज की प्रवासी नाव से टक्कर में 15 लोगों की मौत

एजेंसी

एथेंस । ग्रीस और तुर्किये के मध्य स्थित एजियन सागर में चियोस द्वीप के तट पर ग्रीक कोस्ट गार्ड के एक गश्ती जहाज एवं प्रवासियों और शरणार्थियों को ले जा रही एक नाव के बीच टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 14 के शव समुद्र से बरामद किए गए। ग्रीक नेशनल ब्रॉडकास्टर ईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार, बचाए गए 24 प्रवासियों में से एक की पास के अस्पताल में चोटों के कारण मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में 11 पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। यह दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार रात लगभग 9:00 बजे हुई। घायलों में कई बच्चे और दो गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। दोनों महिलाएं चोट सह नहीं पाईं और कथित तौर पर गर्भपात हो गया। नेशनल

इमरजेंसी एड सेंटर के अनुसार, बचाए गए ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आईं। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। इस अभियान में चार कोस्ट गार्ड जहाज, स्वयंसेवी गोताखोरों को ले जा रही एक निजी नाव और एक हेलेनिक वायु सेना का हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ग्रीक के सरकारी रेडियो ईपीटी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, घायलों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। रात लगभग 12 बजे घायलों में से एक महिला को चियोस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में दस बच्चे हैं। इसी बीच, दो कोस्ट गार्ड अधिकारी भी घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ओइनौसेस के मेयर जियोर्गोस डैनियल ने कहा कि गश्ती जहाज ओइनौसेस में था। उसी ने प्रवासी नाव को देखा। ग्रीक के समाचार आउटलेट प्रोटोथेमा की रिपोर्ट के अनुसार, चियोस का यह वाकया कोस्ट गार्ड और प्रवासी तस्करों के बीच हुई टक्कर का नतीजा है। कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज पर छोटी नाव पर सवार तस्करों ने ही पैंतरेबाजी करते हुए टक्कर मारी। इससे अफरातफरी मच गई। कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में कई प्रवासी मारे गए। कई घायल हो गए। यह लोग मर्सिनिडी इलाके के बताए गए हैं।

ओली सरकार में संसद में पेश किया गया सोशल मीडिया बिल वापस लेने का निर्णय

एजेंसी

काठमांडू। सुशीला कार्की के नेतृत्व में रहे नेपाल की अंतरिम सरकार ने संघीय संसद से सोशल मीडिया विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री निवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने 'सोशल मीडिया के संचालन, उपयोग और विनियमन से संबंधित विधेयक, 2024' को संघीय संसद से वापस लेने के निर्णय को मंजूरी दी। नेपाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में रहे सरकार ने सोशल मीडिया के नियंत्रण और नियमन के नाम पर यह विधेयक संसद में पेश किया था। उस समय भी प्रतिपक्षी दल माओवादी ही नहीं, बल्कि ओली सरकार को समर्थन कर रहे नेपाली कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने इस बिल का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की थी। आज विधेयक वापस लेने के फैसले की जानकारी सरकार के प्रवक्ता तथा गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसी बिल के विरोध के बाद ही नेपाल में जेन जी विद्रोह की नींव पड़ गई थी, जिसके कारण ओली सरकार को अपदस्थ होना पड़ा था।

नाटो प्रमुख बोले- यूक्रेन समझौते को तैयार, लेकिन रूस हमलों से 'अराजकता' फैला रहा

एजेंसी

ब्रसेल्स/कीव। नाटो महासचिव मार्क रुटे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस-यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा गारंटी और संभावित वार्ता पर अहम बयान दिए। दोनों नेताओं ने कहा कि यूक्रेन किसी स्वीकार्य समझौते की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन रूस के ताजा हमले शांति प्रयासों के लिए नकारात्मक संकेत हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने हालिया ऊर्जा युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए रातभर हमले किए, जिनके 'परिणाम' होने चाहिए। उन्होंने साझेदार देशों से चुप न रहने की अपील की और कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणालियों तथा मिसाइलों से जुड़े लाइसेंस अहम हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लगभग 8 लाख सैनिकों वाली यूक्रेन की सेना मौजूदा सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप है। उनके मुताबिक यूरोपीय संघ की सदस्यता दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है, लेकिन

असली सवाल यह है कि भविष्य में हमले की स्थिति में यूरोप और अमेरिका क्या कदम उठाएंगे।

नाटो प्रमुख रुटे ने यूक्रेन के लिए बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' के तहत यूरोपीय बलों की तैनाती और अमेरिकी बैकस्टॉप को महत्वपूर्ण बताया। रुटे ने उम्मीद जताई कि नाटो देश इस वर्ष हथियार खरीद कार्यक्रम के तहत यूक्रेन के लिए बड़े वित्तीय आवंटन करेंगे। उन्होंने सहयोगियों के बीच 'संतुलित बोझ-वितरण' की भी अपील की। रुटे ने रूस के हमलों को नागरिक ढांचे को निशाना बनाने वाला बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों के बीच अराजकता फैल रही है। उनके अनुसार, यूक्रेन वार्ता के लिए तैयार है, मगर रूस के ताज़ा हमले भविष्य की बातचीत से पहले खराब संकेत देते हैं।

आर्कटिक में सुरक्षा बढ़ाने को नाटो की नई पहल, 'आर्कटिक सेंट्री' मिशन की तैयारी शुरू

एजेंसी

बर्लिन। नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए सैन्य मिशन की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच हाल के महीनों में तनाव देखने को मिला है। नाटो के सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड पावर्स यूरोप (शेप) के प्रवक्ता मार्टिन ओ'डॉनेल ने बताया कि 'आर्कटिक सेंट्री' नाम से एक एनहैंस्ड विजिलेंस एक्टिविटी की योजना पर काम चल रहा है। उनका कहना है कि यह पहल आर्कटिक और हाई नॉर्थ क्षेत्र में नाटो की रणनीतिक मौजूदगी और सतर्कता को और मजबूत करेगी। हालांकि, मिशन के स्वरूप और तैनाती से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। आर्कटिक को लेकर चर्चा तब तेज हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की बात कही थी। दिसंबर में उनके बयानों

से ट्रांसअटलांटिक गठबंधन में असहजता बढ़ी थी। बाद में उन्होंने नाटो प्रमुख मार्क रुटे के साथ एक 'फ्रेमवर्क' समझौते का जिक्र करते हुए अपने रुख में नरमी दिखाई। नाटो का कहना है कि आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती सक्रियता भी सुरक्षा दृष्टि से चिंता का विषय है, जिसके चलते क्षेत्र में सामूहिक उपस्थिति बढ़ाना जरूरी हो गया है। इधर डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है और 1951 की उस संधि की पुनर्समीक्षा की संभावना जताई है, जो ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को नियंत्रित करती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी संकेत दिए हैं कि नाटो देश आर्कटिक, खासकर ग्रीनलैंड के आसपास, स्थायी सुरक्षा उपस्थिति के पक्ष में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की सामरिक और आर्थिक अहमियत बढ़ रही है, जिससे वैश्विक शक्तियों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नाटो का यह नया मिशन आने वाले समय में भू-राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

नेपाल में एलपीजी की भारी किल्लत, घंटों लाइन में लगने पर भी नहीं मिला रहा सिलेंडर

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के एलपीजी उपभोक्ता पिछले दो सप्ताह से रसोई गैस की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे घरों और छोटे व्यवसायों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।नेपाल के टैंकर भारत से गैस की आपूर्ति समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। इससे पहले मधेशी दलों के नाकाबंदी के दौरान भी काठमांडू समेत देश के विभिन्न हिस्सों में गैस की भारी किल्लत और लंबी कतारें देखने को मिली थीं। प्रतिदिन सैकड़ों एलपीजी उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर काठमांडू के बालाजू औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल गैस कार्यालय पहुंच रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि लंबी कतार में खड़े रहने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। नेपाल गैस के कार्यकारी संचालक तथा नेपाल एलपीजी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष गोकुल भंडारी ने बताया कि

नेपाल में एलपीजी की दैनिक मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन बाजार में कुछ गड़बड़ी होने के कारण स्थिति को सामान्य होने में कुछ दिन लगेंगे। भंडारी ने बताया कि नेपाल में एलपीजी की प्रतिदिन लगभग 8 हजार सिलेंडर की खपत होती है, जो सर्दियों के महीनों में और बढ़ जाती है। उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में जितनी मांग है, उससे अधिक गैस बाजार में उपलब्ध है, इसलिए घबराने की कोई स्थिति नहीं है।

नेपाल ऑयल निगम ने नेपाल गैस सहित कुछ अन्य गैस कंपनियों के बाजार में गंभीर कमी की जानकारी होने की बात कही है। निगम के प्रवक्ता मनोज ठाकुर ने बताया कि कमी को जल्द दूर करने के लिए उद्योगपतियों को निर्देश दिए गए हैं। ठाकुर ने कहा, 'नेपाल गैस सहित कुछ कंपनियों में समस्या देखी गई है। पाया गया कि वे भारत से समय पर आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। गैस लाने के लिए उनके अपने परिवहनकर्ता नहीं हैं, जो भी हैं वे भारतीय हैं।

हम उन्हीं पर निर्भर हैं। यदि समय पर परिवहन उपलब्ध नहीं हुआ तो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, और फिलहाल ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अभी उद्योगपतियों को बुलाकर कमी दूर करने पर चर्चा की जा रही है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भी निगम बातचीत कर रहा है। ' नेपाल गैस कार्यालय में फिलहाल सुबह से दोपहर 2 बजे तक ही गैस का वितरण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं की लंबी कतारें आम दृश्य बनी हुई हैं।

विमानवाहक पोत की ओर बढ़ रहा था ईरानी ड्रोन, अमेरिका ने हवा में ही किया नष्ट

एजेंसी

वॉशिंगटन/मध्य पूर्व। अमेरिकी सेना ने अरब सागर में अपने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार ड्रोन 'आक्रामक तरीके' से पोत की ओर बढ़ रहा था और उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, जिसके बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने बताया कि अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले एफ-35सी लड़ाकू विमान ने ड्रोन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही सैन्य उपकरणों को क्षति हुई।

यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि समझौता न होने की स्थिति में हालात बिगड़ सकते हैं। इसी बीच, सेंट्रल कमांड ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़े नौकाओं और एक ड्रोन ने अमेरिकी झंडे वाले एक व्यापारी जहाज के करीब तेज रफ्तार से पहुंचकर उसे रोकने और कब्जे में लेने की धमकी दी। विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और तनाव आने वाले दिनों में अमेरिका-ईरान संबंधों को और संवेदनशील बना सकते हैं, खासकर तब जब दोनों देश बातचीत की संभावनाओं को भी टटोल रहे हैं।

क्लिंटन दम्पति आखिरकार जेफरी एपस्टीन जांच में बयान देने के लिए सहमत

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी पूर्व विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन आखिरकार कांग्रेस की जेफरी एपस्टीन जांच में व्यक्तिगत रूप से गवाही देने के लिए अपनी सहमति दे दी है। क्लिंटन दंपति ने यह सहमति हाउस में कांग्रेस की अवमानना ??मत से बचने के लिए दी है। अभी यह साफ नहीं है कि हाउस ओवरसाइट चेयरमैन जेम्स कोमर इस आखिरी समय पर सहमति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। दोनों इससे पहले महीनों तक गवाही देने से बार-बार इनकार करते रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार क्लिंटन के प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कोमर को एक चुनौती भरे 'एक्स' पोस्ट में कहा, उन्होंने सद्भावना से बातचीत की, आपने नहीं की। बावजूद इसके पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश सचिव इस अवसर मौजूद रहेंगे। वे एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, जो सभी पर लागू हो। इसके बाद कोमर ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि उनके अभी भी इस प्रस्ताव पर कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा, क्लिंटन के वकील ने कहा है कि वे शर्तों से सहमत हैं, लेकिन उन शर्तों में एक बार फिर स्पष्टता की कमी है। उन्होंने गवाही के लिए कोई तारीख नहीं बताई है। उन्होंने शर्तों से सहमत होने की बात सिर्फ इसलिए कही है, क्योंकि हाउस ने अवमानना की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। उन्होंने कहा, मैं उन शर्तों को साफ करूंगा जिनसे वे सहमत हो रहे हैं और फिर अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ अगले कदमों पर चर्चा करूंगा। हालांकि, ओवरसाइट कमेटी के टॉप डेमोक्रेट ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें पैनल के चेयरमैन प्रस्ताव को स्वीकार न करें। उन्होंने कहा कि क्लिंटन ने कोमर की सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। रिपब्लिकन रॉबर्ट गार्सिया ने कहा, हमने पहले दिन से ही कहा है कि हम चाहते हैं कि बिल क्लिंटन ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही दें। मुझे खुशी है कि वे गवाही देने जा रहे हैं। कोमर ने क्लिंटन की कानूनी टीम से कहा, जब आपके मुवक्किल को पहली बार कमेटी का समन मिला था, तब से लगभग छह महीने हो गए हैं। क्लिंटन की विशेष सुविधा पाने की लालसा निराशाजनक है और अमेरिकी लोगों की पारदर्शिता की इच्छा का अपमान है। हाउस रूल्स कमेटी की चेयरपर्सन वर्जीनिया फॉक्स ने घोषणा की कि मौजूदा हालात को देखते हुए पैनल अवमानना प्रस्तावों को आगे बढ़ाने से रुकेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर रात भर में कोई और प्रगति नहीं होती है, तो अवमानना प्रस्ताव पर फिर से विचार होगा। बताया जा रहा है कि क्लिंटन की टीम कई दिनों से इस मामले से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी।

रूस प्रतिबंधों पर सहयोग बढ़ाने की कोशिश, ईयू दूत 26 फरवरी को किर्गिस्तान दौरे पर

एजेंसी

बिश्केक/ब्रसेल्स। किर्गिस्तान ने जानकारी दी कि यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिबंध मामलों के दूत डेविड ओ'सुलिवन 26 फरवरी को बिश्केक का दौरा करेंगे। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब हालिया रिपोर्टों में कहा गया कि यूरोपीय संघ किर्गिस्तान को कुछ वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। आरोप है कि इनका इस्तेमाल रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचने में हो सकता है।

किर्गिस्तान सरकार के बयान के मुताबिक उप-प्रधानमंत्री दानियार अमांगेल्दियेव और ईयू दूत ओ'सुलिवन के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने प्रतिबंध से जुड़े मुद्दों पर 'रचनात्मक और सार्थक संवाद' जारी रखने पर सहमति जताई। सरकार ने कहा कि आगे की विस्तृत चर्चा ओ'सुलिवन की

बिश्केक यात्रा के दौरान होगी। इस दौरे को दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ाने और व्यापार से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्टता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार यूरोपीय संघ अपने 'एंटी-सैंक्शंस एवेजन' तंत्र का इस्तेमाल करते हुए कुछ श्रेणियों के सामान के निर्यात पर रोक जैसे सख्त कदमों पर विचार कर रहा है। हालांकि, किर्गिस्तान ने संकेत दिया है कि वह ईयू के साथ सहयोग और संवाद के जरिए समाधान चाहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य एशिया के देशों के साथ ईयू की बातचीत आने वाले समय में और तेज हो सकती है, क्योंकि रूस से जुड़े प्रतिबंधों के अनुपालन को लेकर यूरोप सतर्क रुख अपनाए हुए है।

विश्व बैंक नेपाल के छोटे तथा मझोले उद्यमों को देगा 9.5 लाख अमेरिकी डॉलर सहायता

एजेंसी

काठमांडू। विश्व बैंक ने नेपाल के छोटे तथा मझोले उद्यमों (एसएमई) की वित्तीय मदद करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 9 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से एक लाख से अधिक एसएमई के लाभान्वित होने की उम्मीद है। मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लिए विश्व बैंक के देशीय निदेशक डेविड सिस्लेन ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से वित्तीय पहुंच को सरल बनाकर और व्यावसायिक बाधाओं को कम करके वित्तीय समावेशन के विस्तार में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, 'यह परियोजना जमा एवं ऋण सुरक्षा कोष को सुदृढ़ करने, जोखिम-साझेदारी का विस्तार करने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसाय जैसे कम वित्तीय पहुँच वाले क्षेत्रों के लिए सहायक सिद्ध होगी। ' उन्होंने बताया कि यह पहल एमएसएमई को क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने में मदद करेगी और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन में योगदान देगी। बताया गया है कि 'सतत एवं समावेशी वित्त परियोजना' (एसआईएफ) विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2024 में पूर्ण हुई वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के लिए वित्त संबंधी विकास नीति ऋण (डीपीसी) श्रृंखला के अंतर्गत किए गए सुधारों की निरंतरता है।

ट्रंप ने रिपब्लिकन से भविष्य के चुनाव का राष्ट्रीयकरण करने का किया आह्वान

एजेंसी

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन से भविष्य में होने वाले चुनाव का राष्ट्रीयकरण करने का आह्वान किया है। उनका संदेश ऐसे समय पर आया है, जब उनका प्रशासन इस साल के आखिर में होने वाले अहम मध्यावधि चुनाव से पहले नियमों में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के पूर्व उप निदेशक डैन बोंगिनो से एक पॉडकास्ट में कहा, रिपब्लिकन को कहना चाहिए कि हम मध्यावधि चुनाव में कम से कम 15 जगहों पर जीतेंगे। उन्हें इस बार का चुनाव राष्ट्रीय भावना से लड़ना चाहिए। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी एफबीआई की जॉर्जिया के फुल्टन काउंटी में एक चुनाव कार्यालय की तलाशी के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आई है।

यह चुनाव कार्यालय लंबे समय से ट्रंप के इस बेबुनियाद दावे का केंद्र रहा है कि 2020 में बाइडेन से उनकी हार धोखाधड़ी वाली थी। यह तलाशी अभियान न्याय विभाग के चुनाव रिकॉर्ड को जब्त करने और काउंटी में कथित मतदान में धोखाधड़ी की जांच करने के प्रयास से जुड़ा था। ट्रंप ने कहा, हमारे पास ऐसे राज्य हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं और वह मतगणना में हेराफेरी करते हैं। जहां मेरी जीत हुई, वहां मेरी हार दिखाई गई। अब आप जॉर्जिया में ऐसा देखेंगे। हम अदालत के आदेश से मतदान पत्र हासिल करने में सफल हो गए है।

राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गैबार्ड ने कहा कि ट्रंप ने खुद उन्हें विवादित तलाशी अभियान के लिए अटलांटा जाने का निर्देश दिया था। मैंने राष्ट्रपति की बात तलाशी अभियान में शामिल कुछ एफबीआई एजेंट से भी करवाई। ट्रंप ने इस दौरान हौसला बढ़ाया। महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका में चुनाव राज्य और स्थानीय अधिकारी करवाते हैं। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत कम होती है। ट्रंप चुनाव कराने के इस तरीके को बदलने की कोशिश में सफल होते दिख रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप वैसे भी पिछले साल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसमें मतदान के समय मतदाता को अमेरिकी नागरिकता का साक्ष्य दिखाना होगा। साथ ही राज्य चुनाव के बाद डाक मतपत्रों को नहीं गिन पाएंगे। हालांकि, संघीय अदालत ने इस पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कई मौकों पर ट्रंप ने देश में वोटिंग के तरीके को बदलने का वादा करते रहे हैं। उन्होंने अगस्त में कहा था कि वह डाक मतपत्रों की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाएंगे। मतदान के लिए वोटिंग मशीन को अनिवार्य किया जाएगा। राष्ट्रपति ने नवंबर के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन को अमेरिकी हाउस में और सीटें जीतने में मदद करने के मकसद से मिड-डेकेड रीडिस्ट्रिक्टिंग कैंपेन भी शुरू किया है। न्याय विभाग ने दावा किया है कि बिना साक्ष्य वाले अप्रवासी अमेरिकी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए घुसपैठ कर चुके हैं। विभाग ने दो दर्जन राज्यों की मतदाता सूची पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा भी किया है। अदालत से मांग की गई है कि सामाजिक सुरक्षा नंबर और घर का पता जैसी निजी जानकारी भी सूची में शामिल कराई जाए। कहा जा रहा है कि कुछ डेमोक्रेटिक चुनाव अधिकारियों ने मध्यावधि चुनाव में ट्रंप प्रशासन की संभावित दखल को रोकने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

मिनेसोटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव साइमन ने पिछले महीने के आखिर में कहा था कि चुनाव के तौर-तरीकों को बदलने का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है।

page 1 and 8 Feb 5_page 1 Mar 25 final ds.qxd 2/5/2026 12:27 AM Page 2

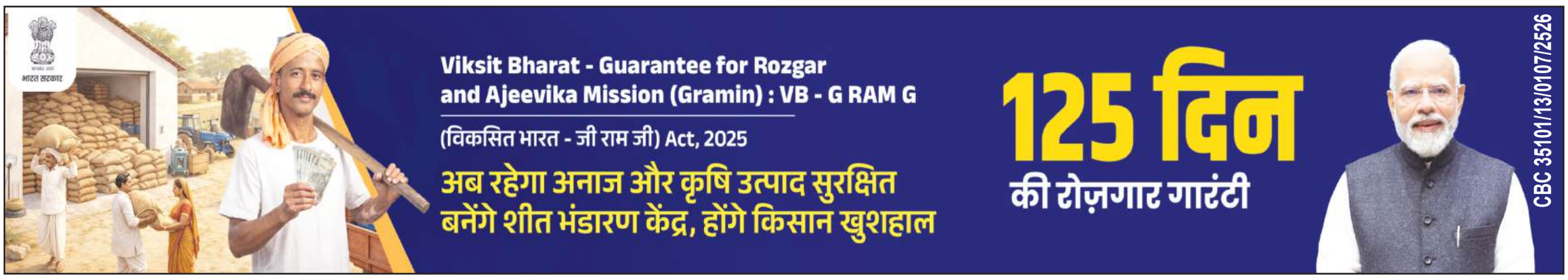

कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के चलते फंसे 35 वाहनों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला

कुपवाड़ा, 04 फ़रवरी (हि.स.)। कुपवाड़ा जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते फंसे 35 वाहनों को जिला प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह राहत एवं बचाव अभियान मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि से शुरू होकर पूरी रात जारी रहा।

अधिकारियों के अनुसार जिले के ऊँचाई वाले क्षेत्र सदना टॉप में अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण कई वाहन रास्ते में फंस गए थे। सूचना मिलते ही कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदना टॉप पर रेस्क्यू और निकासी अभियान शुरू किया। खराब मौसम और कम दृश्यता के बावजूद प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी से अभियान में जुटी रहीं। भारी मात्रा में जमी बर्फ के कारण वाहनों को निकालने का कार्य चुनौतीपूर्ण था लेकिन टीमों ने तड़के सुबह तक लगातार प्रयास करते हुए सभी 35 फंसे वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बर्फ हटाने वाली मशीनों और फील्ड स्टाफ को मौके पर तैनात किया गया था। सबसे अधिक संवेदनशील और जोखिम भरे हिस्सों को प्राथमिकता के आधार पर साफ किया गया, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने कहा कि समय पर की गई कार्रवाई से हालात को और बिगड़ने से रोका जा सका और आंशिक रूप से यातायात बहाल करने में भी सफलता मिली।

गौ-तस्करी प्रयास विफल, 18 मवेशी छुड़ाए, ट्रक जब्त

कठुआ, 04 फरवरी (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने गौ-तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग लखनपुर पर गौ-तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 18 मवेशियों को सुरक्षित बचाया और एक ट्रक को मौके से जब्त किया। यह कार्रवाई थाना लखनपुर की पुलिस टीम द्वारा नाका जांच के दौरान की गई। पंजाब से श्रीनगर की ओर जा रहे संदिग्ध ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान ट्रक में मवेशियों को अमानवीय तरीके से ले जाया जा रहा था। मामले में थाना लखनपुर में एफआईआर नंबर 12/2026 धारा 223 बीएनएस व 11 पीसीए एक्ट के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक कठुआ के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से गौ-तस्करों में हड़कंप मच गया है। कठुआ पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि गौ-तस्करी से संबंधित किसी भी सूचना को पुलिस के साथ साझा करें, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

समर्पण दिवस से पहले अशोक कौल ने पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा की

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। भाजपा जम्मू-कश्मीर के महासचिव (संगठन) अशोक कौल ने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक व्यापक संगठनात्मक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पहुंच का आकलन किया गया। उनके साथ भाजपा जम्मू-कश्मीर के महासचिव संजीता डोगरा, बलदेव सिंह बिल्लावारिया और गोपाल महाजन भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और विभिन्न स्तरों पर की जा रही संगठनात्मक गतिविधियों और जन संपर्क पहलों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी। विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य जनता के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने और इसकी संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कौल ने केंद्रीय बजट 2026 जनजागरण अभियान, वीबी ग्राम जी और अन्य पार्टी पहलों के तहत आयोजित सम्मेलनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन चौपालों, विधानसभा सम्मेलनों और युवा, किसान और महिला सम्मेलनों सहित विशेष जन संपर्क कार्यक्रमों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कार्यक्रम में अनुशासन, उद्देश्य की स्पष्टता और वैचारिक प्रतिबद्धता झलकनी चाहिए। कौल ने कहा कि भाजपा की ताकत उसकी सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली में निहित है।

जम्मू पुलिस ने दो चोरी के मामले सुलझाए

जम्मू, 04 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने निरंतर जांच और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से चिनोर में दो अलग-अलग चोरी के मामलों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और चोरी की संपत्ति बरामद हुई।

27 नवंबर 2025 को पुलिस चौकी चिनोर में अब्दुल रहमान के पुत्र अब्दुल हाफ़िज़ निवासी थथर बन तालाब जम्मू से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके घर में सेंध लगाई और लगभग 20 तोला सोने के आभूषण चुरा लिए। तदनुसार पुलिस स्टेशन डोमाना में धारा 331(3)/305 बीएनएस

के तहत एफआईआर संख्या 248/2025 दर्ज की गई और जांच पुलिस चौकी चिनोर के प्रभारी पीएसआई अर्जुन सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। निरंतर और अथक प्रयासों के बाद पुलिस चिनोर की टीम ने तीन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जिनकी पहचान भदर अली पिता शेर मोहम्मद, निवासी केरन, बन तालाब, जम्मू, बंटी पिता राम पॉल, निवासी मकान नंबर 702, सेक्टर नंबर 3, भगवती नगर, तालाब टिल्लो, जम्मू और रियाज अहमद पिता मजीद अहमद, निवासी थाथर, बन तालाब, जम्मू के रुप में हुई।

जैविक खाद- रसायनिक खादों का सार्थक विकल्प

भारतीय कृषि में हरित क्रांति के बाद आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ने के साथ-साथ उसी अनुपात में पौध संरक्षण रसायनों व उर्वरकों का उपयोग भी अधिकाधिक होने लगा है। यद्यपि आज देश खाद्यानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है परन्तु आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से हमारी मृदा की संरचना तथा वातावरण में भाई असमानता व असंतुलन पैदा हो रहा है। अब हमारे देश में भी अन्य विकसित देशों की भांति कार्बनिक व प्राकृतिक खेती की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

जैविक खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक के वातावरण के साथ जुडी हुई है। यह खेती की एक ऐसी समूह पद्धति है जिसमें उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के लिए घास-फूस से बनी कम्पोस्ट, शहरी कचरे व गंदे नाले से प्राप्त गली-सड़ी खाद, जीवाणु खाद तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से निर्मित खाद, नीम के पौधे के विभिन्न उत्पाद तथा प्रक्रति में पाए जाने वाले अन्य पौधों के उत्पादों से पौध संरक्षण का काम लिया जाता अहि। रसायनों से होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जैविक संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। मैं विषय के दायरे में रह कर यहाँ सिर्फ रासायनिक खादों के विकल्प के बारे में ही बात करूँगा।।

रासायनिक खादों के विकल्प के लिए जैविक खादें

1. **देशी खाद/गोबर की खाद**
2. **हरी खाद**
3. **कचरे (शहरी व ग्रामीण की खाद/कम्पोस्ट**
4. **केंचुआ खाद**
5. **जीवाणु खाद आदि**

देशी खाद अधिकांश किसान गोबर को गौशाला से सीधे ही खेतों में फेक दिया जाता है या फिर खेतों के किनारे पर बिना गड्ढा बनाये ढेर लगा दिया जाता है जिससे गोबर में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व वर्षा के पानी से बह जाते हैं फिर कुछ तत्व धूप की गर्मी से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये कच्चा गोबर फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप भी पैदा करता है। अगर किसान भाई इस खाद को गड्ढे में बनाएं तो इसमें विभिन्न पौध पोषण तत्वों की मात्रा दो से तीन गुणा ज्यादा होती है। गड्ढों/ टैंक या तो जमीन से नीचे या सतह के ऊपर बनाये जा सकते हैं। इन गड्ढों में तीन से चार मास के भीतर खाद बनकर तैयार हो जाती है। अच्छी खाद बनाने का ढंग व उसके उचित प्रयोग के बारे में निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखें

सबसे पहले गौशाला से कुछ ही दूरी पर या अपने खेत के एक कोने पर एक या 2 मीटर लम्बा, 2 मीटर चौड़ा तथा के मीटर गहरा गड्ढा खोदें। उसके अंदर की तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबाएँ ताकि पानी का कम से कम रिसव हो। उसके बाद रोजाना गोबर और पशुओं के नीचे बिछाएं बचे घास-फूस को गड्ढे में डालते जाएं और जहाँ तक सम्भव हो सके पशुओं के मूत्र को भी उसी गड्ढे में गोबर के साथ-साथ अवश्य डालते रहें मूत्र में गोबर और मूत्र के कुल भाग का 95% पोटाश, 63% नाइट्रोजन और 50% गंधक जैसे तत्व होते हैं। पशुओं के बांधने का ऐसा तरीका भी अपनाया जा सकता हैं कि सभी पशुओं का मूत्र एक नाली से होता हुआ लगातार खाद के गड्ढे में गिरता रहे। यही मूत्र सूखे घास और गेंहू के भूसे के बिछावन में भी सोख लिया जा सकता है। पूरे बिछौने और गोबर को भी गड्ढे में डाला जा सकता है। जब यह गड्ढा भरते-भरते जमीन की सतह से लगभग डेढ़ फुट ऊपर तक भर जाए तो उसमें चार पांच बाल्टी पानी डालकर मिट्टी और गोबर के मिश्रित लेप को एक इंच मोटी तह जमा दें। ऐसा करने से गोबर की खाद में नमी अधिक बनी रहेगी और गलन-सड़न की प्रतिक्रियाएं तेजी से काम करेंगी और मक्खियों का प्रकोप भी कम होगा। चार-पांच मास के बाद खाद तैयार हो जायगी।

जब इस खाद का प्रकोप करना हो तो गड्ढे को फसल की बीजाई से एक महीना पहले खोलकर निरीक्षण करें। अगर खाद पूर्ण रूप से गली-सड़ी न हो तो उसे खेत में बीजाई के दो तीन सप्ताह पहले एक समान रूप से फैलाकर तथा हल चलाकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें ताकि सही अर्थ में पोषक तत्वों के भण्डार सिद्ध हो सकें। यदि खाद अच्छी तरह से गली-सड़ी हो तो बीजाई के केवल एक या दो पहले भी खेत में डाली जा सकती है। अति उत्तम गोबर की खाद बनानी हो तो गोबर को गड्ढे में भरते समय कुछ दिनों के अन्तराल पर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का बुरकाव करते रहें क्योंकि ऐसा करने से खाद में फास्फोरस तत्व की मात्रा तो बढ़ती ही है साथ में नाइट्रोजन की होने वाली हानि पर भी रोक लग जाती है। यह ध्यान रखें कि केवल गोबर की खाद डालने से फसलों की आवश्यकता के सभी तत्व संतुलित मात्र में उपलब्ध नहीं होते हैं, विशेषकर फास्फोरस इत्यादि। फसलों की अधिकतम पैदावार लेने के लिए रासायनिक खादों का भी सही मात्रा में प्रयोग करें। परन्तु इसके लिए अपने खेती की मिट्टी का परीक्षण जरुर करवाएं।

हरी खाद मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु व् मिट्टी की ऊपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले-सड़े हरे पौधे (दलहनी एवं अन्य फसलों अथवा उनको भाग) को जब मृदा की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते है।

आदर्श हरी खाद फसल के गुण

हरी खाद के मुख्य चार गुण है

क) उगाने में न्यूनतम खर्च

ख) न्यूनतम सिंचाई, कम से कम पादप संरक्षण

ग) खरपतवारों को दबाते हुए जल्दी बढ़त प्राप्त करें तथा विपरीत परिस्थतियों में उगने की क्षमता हो।

घ) कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करती हो।

1. हरी खाद केवल नत्रजन व कार्बिनक पदार्थों का ही साधन नहीं है बल्कि नहीं है बल्कि इससे मिट्टी में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।

2. हरी खाद के प्रयोग में मृदा में सुधार एवं मृदा भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी, जलधारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता/क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी होती है।

3. हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।

4. हरी खाद में मृदाजनित रोगों में भी कमी आती है।

5. इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं।

क) फलीदार फसल में पानी की काफी मात्रा होती है परन्तु अन्य फसलों में रेशा काफी होने की वजह से मुख्य फसल (जो हरी खाद के बाद लगानी हो) में नत्रजन की मात्रा काफी कम हो जाती है।

ख) क्योंकि हरी खाद वाली फसल के गलने के लिए नमी आवश्यकता पड़ती है अत: कई बार हरी खाद के पौधे नमी जमीन से लेते हैं जिसके कारण अगली फसल में सूखे वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती है।

हरी खाद के व्यवहारिक प्रयोग

क) उन क्षेत्रों में जहाँ नत्रजन तत्व की काफी कमी हो।

ख) जिस क्षेत्र की मिट्टी में नमी की कमी कम हो।

ग) हरी खाद का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्र में न करें। इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण मुख्य फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी अवस्था में नमी के संरक्षण के अन्य तरीके अपनाएं।

घ) जिनके तने तथा जड़ें काफी मात्रा में पानी प्राप्त कर सकें।

ड) ये वे फसलें होनी चाहिए जो जल्दी ही जमीन की सतह को ढक लें चाहे जमीन रेतीली या भारी या जिसकी बनावट ठीक न हों में ठीक प्रकार बढ़ सकें।

च) जब ऊपर बतायी बातें फसल में विद्यमान हों तो फलीदार फसल का प्रयोग अच्छा होता है क्योंकि उन फसलों से नत्रजन भी प्राप्त हो जाती है।

कम्पोस्ट खाद किसानों व बागवान भाइयों के लिए यहाँ पर कुछ खादें बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। इस सन्दर्भ में यहाँ बताना उचित होगा कि जो भी खाद कार्बिनक पदार्थ के सड़ने से तैयार की जाती है उसे कम्पोस्ट कहते हैं। गोबर से बनी खाद फार्म यार्ड मैन्योर को कम्पोस्ट कहते हैं। इसलिए आगे के लेख में खाद शब्द का प्रयोग कम्पोस्ट के लिए ही किया गया है। चाहे वह गोबर से या पेड़ पौधों के पत्तों से या इन दोनों के मिश्रण से बनी हो खाद या कम्पोस्ट ही कहलायेगी।

कम्पोस्ट खाद बनाने की विधियाँ

क) ऐडको विधि

हटचिन्सन और रिचर्डसन ने 1921 में विधि इंग्लैंड में विकसित की थीझ इस विधि में पराल, डंठल, घास और खेत खलिहानों के पदार्थ जिनका अन्य कोई उपयोग नहीं होता कम्पोस्ट बनाने के प्रयोग में लाये जाते हैं। इसके तैयार करने मने एड्को चूर्ण प्रयोग में लाया जात है जिसे 'एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट कम्पनी ऐडको' तैयार करती और बेचती है। एक टन सूखे कचरे के लिए 60 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 30 ग्राम सुपरफास्फेट, 25 ग्राम म्यूरेट ऑफ़ पोटाश और 50 ग्राम चूना पत्थर पिसा हुआ डाला जाता है। दस फुट वर्ग क्षेत्र में सुखी घास या पराल या इसी प्रकार का अन्य मोटा कचरा 12 इंच मोटी तह में एक सा बिछा देते हैं। फिर उसे पानी में भिगों दिया जाता अहि। भींगे पदार्थ पर एड्को चूर्ण आवश्यक मात्रा में फैला देते हैं। इस तह के ऊपर और दूसरी तह कचरे की डालकर भिगोकर उस पर फिर एड्को चूर्ण डाल देते हैं। इस तहर ढेर को पूरा करने के लिए एक के ऊपर दूसरी तह डालते जाते हैं। एक गड्ढे में लगभग एक टन सूखा कचरा रखते हैं जो कि गड्ढे की ऊंचाई (छ: फुट) से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे मोटी तह के लिए हवा के अंदर जाने और बाहर आने में कठिनाई होती है। इसे तीन सप्ताह तक ऐसे ही छोड़ देते हैं परन्तु आवश्कता पड़ने पर पानी पर पानी डाल देते रहना चाहिए। प्रति बार एक हजार लीटर तक पानी देना चाहिए। चार से छ: मास में कम्पोस्ट तैयार हो जाती है। यदि जरूरत हो तो बीच में एक बार ढेर को उलट फेर कर देना चाहिए। भारतवर्ष जैसे गर्म देश के लिए यह विधि बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है तथा तापमान भी जितना चाहिए वह भी एक सार नहीं रहता बल्कि कम या ज्यादा होता रहता है। सक्रियता कम्पोस्ट विधि के अविष्कार करने वाले बंगलूर के फाउलर और रेगे हैं जिन्होंने इस विधि को 1923 ई. में विकसित किया। घास, घास-पात, पत्ते, बाग़ बगीचों, खेत खलिहानों और घर के कचरे को एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। फिर समय मिलने पर इस कचरे को ढेर से निकाल आकर छ: फुट लम्बे-चौड़े और दो फुट ऊँचे एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं। जरूरत हो तो कचरे को प्रवाह, सीवेज और स्लज, के उपयोग से अधिक अच्छी कम्पोस्ट बनती है। इन सबसे आधी कम्पोस्ट मनुष्य के मल-मूत्र से तैयार होती है। यदि कचरे में हड्डी का चुरा मिला दें तो ज्यादा अधिक लाभप्रद कम्पोस्ट तैयार हो जाती है। ज्यों ही किव्वन समाप्त हो जाए ढेर का एक तिहाई भाग निकाल कर एक गड्ढे में सुरक्षित रखना चाहिए और शेष तो तिहाई में ताजा सूखा कचरा मिलाकर विधि को दोहराना चाहिए। इंदौर के फार्म पर काम करने वाले हार्डवर्ड इस विधि को विकसित करने वाले हैं। इस विधि से गोबर की कम मात्रा से काम चल जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी विधि समझी जाती है और इसका प्रयोग सारे संसार में हो रहा है। इस विधि के लिए गड्ढों का इस्तेमाल होता है। ये गड्ढे बंगलौर में 30'×14'×2' जे थे। इनका किनारा ढलानदार तथा ताकि बैलगाड़ियाँ या ट्रैक्टर गड्ढे में आ जा सकें गड्ढे दो-दो के समूह में साथ-साथ बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े गड्ढों के बीच 12 फूट की दूरी रहती है। एक टंकी में ज रहना है जिसमें 3000-3200 लीटर पानी आ सकता है। टंकी जमीन में 4' की ऊंचाई रपर रहती है ताकि उससे बहकर पानी सरलता से गड्ढे में जा सके। एक टंकी छ: गड्ढों के लिए प्रयोग होती है। खाद बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं वे हैं

क) पेड़ पौधों के पत्ते या बारीक शाखाएं जो किसी अन्य उपयोग के न हों, घास-पात, पेड़ से गिरा पत्ता, हल्का छांटन, झाड़ियों और पेड़ों की कतरन, पराल, भूसा, लकड़ी की छीलन, लकड़ी का बुरादा, रद्दी कागज, पुराना सड़ा गला बोरा व कपड़ इत्यादि। जो पदार्थ कड़ा अरु लकड़ी की तरह कठोर है उसे काट-काटकर अथवा कुचल कर छोटा या मुलायम बना लेते है। हरे कार्बिनक पदार्थ को सूखा कर इकट्ठा करते हैं।

ख) गाय, बैल व भैस का गोबर अथवा घोड़े की लीद अस्तबल या गौशाला का कचरा भी इसमें मिलाया जा सकता है।

ग) मूत्र वाली मिट्टी- जहाँ पशु रहते हैं वहां की मिट्टी तीन-तीन महीने पर करीब 6 इंच तक खोद कर निकाल लेनी चाहिए और कम्पोस्ट के गड्ढे के निकट इकट्ठा करना चाहिए जहाँ से मिट्टी निकाली हो वहां फिर ताज़ी मिट्टी भर देनी चाहिए।

घ) लकड़ी की राख- इससे अम्लता दूर होती है तथा इसमें पोटाश की मात्रा भी बढ़ती है।

ड) जल और वायु- इससे खाद में हयूमस बनता है। जीवाणु और कवक ही ह्यूमस बनाते हैं। इन जीवाणुओं और कवकों के लिए जल और वायु आवश्यक होते हैं।

च) कम्पोस्ट के लिए गड्ढा भरने की विधि

छ) गड्ढे के ऊपर एक तख्ता रख लेते हैं ताकि गड्ढे को कचरे से बिना कुचले भर सकें। कचरे को पहले 3 इंच मोटी तह बनाकर समतल कर लेते हैं। उस पर राख और मूत्र की मिट्टी को छिड़क देते हैं। उसके ऊपर फिर दो इंच मोटी तह को कूटे गोबर और मैली की हुई बिछाली से भर देते हैं। उसके ऊपर हर रोज पाइप से पानी डालकर उसे भिंगो देते हैं। इसके ऊपर फिर से कचरे और पानी को क्रम-क्रम से डालकर 3 इंच मोटी तह के ऊपर गोबर और बिचाली का एक तह और उसके ऊपर मूत्र मिट्टी और राख बिछाकर पानी छिड़क देते हैं। गड्ढे को शाम को और फिर दूसरे दिन प्रात: भिगोते हैं। पहली बार तीन क्रमों में पानी देने से उसमें इतना पानी रहता है कि उसका तीव्र किव्वन शुरू हो जाता है और गड्ढे का कचरा सिकुड़ का पेदों में चला जाता है। उसके बाद सप्ताह में एक बार सींचना चाहिए। यदि गर्मी ज्यादा हो तो सप्ताह में दो बार सींचना चाहिए।

ज) कचरे में भलीभांति सड़ने और अपक्षय के लिए वायु और जल का रहना आवश्यक है। वायु और जल की प्राप्ति के लिए उसका तीन बार उलट-फेर करना चाहिए। पहला उलट-फेर 10 से 14 दिन के बीच करते हैं। आधे गड्ढे को पंजा (कुदाली) द्वारा खोदते हैं और उस पर पानी देकर भिगोते हैं और बिना खोदे आधे भाग फिर बिछा देते हैं। आधे उलटे हुए ढेर की फिर अच्छी तरह सिंचाई कर देते हैं। दूसरा उलट-फेर 10 से 14 दिन के बाद करते हैं। उसे फिर उलट कर पानी से भिगो कर गड्ढे के दूसरे खाली अंश में ढीला-ढाला रख देते हैं। तीसरा उलट-फेर गड्ढे के तीन मास पुराना होने पर करते हैं। टूटते हुए काले पदार्थों को पानी से भिंगोकर सतह पर आयाताकार ढेर में पैंदे में (10 फुट चौड़ा, ऊपर 9 फूट चौड़ा और साढ़े तीन

फुट ऊँचा) इकट्ठा करते हैं और परिपक्व होने के लिए एक मास छोड़ देते हैं। एक मास के बाद वह इस्तेमाल करने के योग्य हो जाता है। बरसात के दिनों में जब गड्ढे के पानी से भर जाने की आंशका हो तो ढेर को सतह पर लगाते हैं। यदि वर्षा सामान्य हो तो ढेर नीचे 8 फुट +8 फुट और ऊपर । फुट + और गहरा होता है। यदि वर्षा ज्यादा तो तो ढेर के ऊपर छप्पर डालना चाहिए।

घ) भारद्वाज विधि- इस बढ़ी को अखिल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिक डॉ भारद्वाज ने विकसित किया है। इस विधि द्वारा भी कम्पोस्ट, गोबर और दूसरे वनस्पति और नगर और शहरों के कचरे से तैयार किया जाता है। कम्पोस्ट को गड्ढों में बनाया जाता है परन्तु जमीन की सतह पर भी अच्छी कम्पोस्ट तैयार की जा सकती है। कम्पोस्ट का गड्ढा ऊँची जमीन पर बनाना चाहिए जहाँ वर्षा का पानी इसमें इकट्ठा न हो। इस विधि द्वारा खाद 1×1×1 मीटर के गड्ढों में तैयार की जाती है। ये गड्ढे यदि पक्के हों और उनके ऊपर यदि छत पड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है।

(Compiled by: C M Sharma)

कम्पोस्ट बनाने का सामान

1. बृहतकाय कार्बिनक पदार्थ- घास-पात, गोबर, पराल और मक्की, सरसों चना, मटर, सनई, पशु बिछानी, चाय की छांटनी, चीड़ के पत्तों, ढेंचा, खेत खलिहानों का कचरा, सड़को का कूड़ा-करकट, दहलन का छिलका, वृक्षों के पत्ते, खरपतवार और कोई भी कार्बनिक व्यर्थ का पदार्थ हो सकता है।

2. उपयुक्त आरम्भक- कम्पोस्टिंग प्रतिक्रिया के लिए जीवाणु अनुवार्य है जो आरम्भक द्वारा जैसे गोबर, बिष्टा, मल प्रवाह, अवपंक, सक्रिय कृता अवपंक कम्पोस्टिंग कल्चर द्वारा दिए जा सकते हैं। यदि जरूरत है तो अकार्बनिक नाइट्रोजन भी डाला जा सकता है।

3. जल की मात्रा- यह 50-75% रहनी चाहिए। जल की कमी हो जाये उसकी पूर्ति बीच-बीच में करते रहना चाहिए।

4. वायु की मात्रा- यह विच्छेदन के लिए जरुरी है और पर्याप्त मात्रा में

मिलनी चाहिए क्योंकि विच्छेदन वाले अधिकांश जीवाणु वायु जीवी होते हैं। इसके लिए ढेर को उलट-फेर करते रहना चाहिए। कम्पोस्ट बनाने वाले पात्र या गड्ढे के तल में छेद वाली नाली रखी जा सकती है यह बाँस का प्रयोग भी किया जाता है जिससे वायु प्रविष्ट कराई जा सके। यदि कम्पोस्ट बनाने का वायुजीवी उपचार 3-4 माह चलता रहे तो कार्बनिक पदार्थों का टूटना 50: से अधिक हो सकता है जो कि एक अच्छी कम्पोस्ट के लिए जरुरी है।